कमल संदेश
ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिवशक्ति बक्सी

संपादक मंडल

सत्यपाल
संजीव कुमार सिन्हा

कला संपादक

धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय-सूची

हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में बुनकरों की समस्याओं को लेकर भाजपा द्वारा आयोजित अनशन कार्यक्रम के दौरान जनता को सम्बोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी। साथ में अनशन पर बैठे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्री मुरलीधर राव एवं इस अवसर पर उपस्थित हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री बलवीर पुंज एवं आन्ध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जी. किशन रेड्डी।

संसद में बहस

श्रीमती सुषमा स्वराज........ 6
श्री अरुण जेटली........ 8
श्री वेंकैया नायडू........ 10
श्री प्रभात झा........ 11
श्री रुद्र नारायण पाणि........ 24

लेख

सौ शरदों की वाणी मौन क्यों है?
'kkUrk dqekj........ 13
इरादों के पक्के हैं नितिनजी
çHkkr >k........ 16
लोकलुभावन नीतियों के खतरे
cycht iqat........ 18

साक्षात्कार

श्री रविशंकर प्रसाद........ 20

अन्य

सुशासन दिवस पर कार्यक्रम आयोजित........ 23
आंध्र प्रदेश में भाजपा का त्रि–दिवसीय अनशन........ 26
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित........ 30

आत्मा की रोशनी

महर्षि याज्ञवल्क्य और राजा जनक अक्सर जीवन के गूढ़ प्रश्नों पर विचार करते रहते थे। जनक उनके सामने अपने मन की जिज्ञासा रखते और महर्षि उनके समाधान प्रस्तुत करते थे। एक दिन जब दोनों बैठे थे, तब राजा जनक ने सवाल किया, महर्षि! मेरे मन में एक शंका है, हम जो देखते हैं, वह किस ज्योति से देखते हैं? महर्षि ने कहा, राजन! यह क्या बच्चों वाली बात करते हैं आप। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हम सूर्य की रोशनी के कारण देखते हैं। जनक ने फिर पूछा, सूर्य जब अस्त हो जाता है, तब हम किस प्रकाश से देखते हैं? महर्षि बोले, चंद्रमा के प्रकाश में। इस पर जनक ने फिर पूछा, जब चंद्रमा भी न होए नक्षत्र भी न हों, अमावस के बादलों से भरी काली रात हो तब ...? महर्षि ने जवाब दिया, तब हम शब्दों की ज्योति से देखते हैं। विशाल वन है, चारों और अंधेरा है, पथिक मार्ग भूल गया है। वह आवाज देता है, मुझे मार्ग दिखाओ। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, इधर आओ, मैं मार्ग पर खड़ा हूं। और वह व्यक्ति शब्दों के प्रकाश से उस मार्ग पर पहुंच जाता है। जनक ने फिर पूछाए लेकिन महर्षि! जब शब्द न हों, तब हम किस ज्योति से देखते हैंध् इस पर महर्षि ने जवाब दिया, तब हम आत्मा की ज्योति से देखते हैं। आत्मा की रोशनी में ही सारे काम होते हैं। इस उत्तर से राजा जनक संतुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, हां, गुरुदेव! आपने बिल्कुल सही कहा। आत्मा की रोशनी सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य इसी के सहारे अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ता है।

संकलन : ममता जैन (नवभारत टाइम्स)

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को शुभ परिवर्तन का पर्व 'मकर संक्रांति' की हार्दिक शुभकामनाएं

व्यंग्य चित्र

हमें लिखें...

सम्पादक के नाम पत्र

कमल संदेश

सादर आमंत्रित

आपकी राय एवं विचार

सम्पादक,
कमल संदेश
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66
सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
ई-मेल:
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रिय पाठकगण

कमल संदेश (पाक्षिक) का अंक आपको नियमित मिल रहा होगा। यदि किन्हीं कारणवश आपको कोई अंक प्राप्त न हो रहा हो तो आप अपने प्रदेश कार्यालय को या हमें अवश्य सूचित करें।

-सम्पादक

सम्पादकीय

कमजोर सरकार और असहाय प्रधानमंत्री

संसद और देश की राजनीति की स्थिति दयनीय हो चुकी है। सरकार न संसद में दिखती है न सचिवालयों में और न ही मंत्रालयों में। जिसको जो मन आ रहा, वह वही करने लगता है। अराजकता का ऐसा आलम भारत ने कभी नहीं देखा था। छोटी–छोटी पार्टियों के लोग कांग्रेस को कुर्सी से उतारने की धमकी दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस हो या अन्य कोई, प्रधानमंत्री की दया पर नहीं है, बल्कि रेलमंत्री की दया पर है प्रधानमंत्री की कुर्सी। जिस सरकार के प्रधानमंत्री की ऐसी हालत होगी उस देश का हाल क्या होगा? भारत इस समय जबर्दस्त संक्रमण काल से गुजर रहा है। विपक्ष के प्रति सत्तापक्ष की ऐसी दुर्भावना, विरोध एवं उदासीनता का भाव देश ने कभी नहीं देखा। लोकतंत्र के उन संवैधानिक स्तम्भों को दांव पर लगा दिया गया है जिसकी कभी साख हुआ करती थी।

पहली बार देखा जा रहा है कि खबरों का कोई असर नहीं है। खबरें छपती है और संबंधित मंत्रीगण पर कोई असर नहीं होता है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात पर लोगों ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों के लिए यह चुनावी दांव खेल रही है। जनता में यह बात घर कर गई है कि जिस तरह मायावती ने चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश को चार भागों में बांटने का निर्णय लिया वह लोगों को भ्रम में डालकर वोट बटोरने की राजनीति है। हम तो मुस्लिमों से भी कहना चाहते हैं कि वे यूपीए सरकार की नीयत देखें। यूपीए सरकार की नीयत पूर्व से ही खराब है। वह देश को सदैव गुमराह करती रही है। कांग्रेस के वे नेता जिनके सामने देश पहले हैं, वे आजकल परेशान हैं। उनके सामने अस्तित्व का संकट उत्पन्न हो गया है। भाजपा अपनी नीतियों में स्पष्ट है।

उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी का करिश्मा दिख नहीं रहा। वे जब भी उत्तर प्रदेश जाते हैं तो वे कहते हैं देश में युवाओं को आगे आना चाहिए। इसका साफ मतलब है कि श्री राहुल गांधी का संदेश है कि जो बुजुर्ग हैं वे राजनीति से मुक्त हो जाए। यानि डॉ. मनमोहन सिंह जी! आपको सीधे तो कह नहीं सकते इसलिए वे युवाओं को आगे आने की बात कह रहे हैं। काश! डॉ. मनमोहन सिंह राजनीति समझते। एक जानकारी में बात यहां तक आ गई है कि लोग यह कहने लगे हैं कि कांग्रेस के एक महामंत्री ने सोनिया जी और राहुल जी में बहुत गहरा मतभेद पैदा करा दिया है। कांग्रेस अपने उलझन में उलझी हुई है। राहुल गांधी विवाह न होने से दुखी हैं, वहीं कांग्रेस की डूबती नैय्या को कैसे बचाया जाए, इससे वे स्वयं जूझ रहे हैं।

देश की चिंता से दूर कांग्रेस अपनी आंतरिक कोलाहल में डूबी है और उत्तर प्रदेश में अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के नेताओं पर कम भरोसा कर रही है। यह कितना बड़ा मजाक है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास एक भी विश्वसनीय नेता नहीं है। फिर क्या करेंगे राहुल गांधी? क्या किया है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए? भारतीय राजनीति जब राहुल गांधी से सवाल करती है कि आपने राष्ट्र की राजनीति के लिए क्या किया तो उत्तर 'शून्य' ही आता है। देश को समाधान चाहिए समस्या नहीं। हो सकता है कांग्रेस के लिए राहुल गांधी (युवराज) समाधान हों पर देश ने तो उनको एक बहुत बड़ी समस्या ही मान लिया है। ■

महंगाई रोको या गद्दी छोड़ो - सुषमा स्वराज

लोकसभा में महंगाई पर चर्चा के दौरान 8 दिसंबर 2011 को विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज ने कांग्रेसनीत यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने अपने अकाट्य तर्कों और तथ्यों के हवाले से यह साबित कर दिया कि सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। हम उनके भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं :–

गर समय हम सरकार को महंगाई पर झकझोरते रहे हैं पता नहीं क्या कारण है कि आम आदमी के दर्द की परवाह किए बिना आंख मींचकर और कान भींचकर यह सरकार अपनी राह पर चली जा रही है। सरकार ने महंगाई के जाल में फंसे हुए व्यक्ति को आंकड़ों के मकड़जाल में फंसाने की कोशिश की है। महंगाई से मर रहे व्यक्ति का पेट आंकड़ों से नहीं भरता, दानों से भरता है। सरकार ने गरीबी के मानक ही बदल दिए हैं। आपके योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफिया बयान देकर कहा कि शहर में 32 रुपए प्रतिदिन अपने ऊपर खर्च करने वाला व्यक्ति और देहात में 26 रुपए प्रतिदिन खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के बाहर हो गया है। जो व्यक्ति 32रुपए प्रतिदिन शहर में और 26 रुपए प्रतिदिन देहात में अगर अपने पर खर्च करता है तो आप यह समझते हैं कि वह गरीबी रेखा से बाहर है। जो राजकीय सहायता मिलती है, बिलो पावर्टी लाइन वालें को मिलती है, उसकी कतार से उसे बाहर कर दिया जाता है। वह व्यक्ति इस सरकार की निगाह में अमीर हो जाता है। यह ठीक है कि 20 प्रतिशत लोगों की आमदनी इस देश में बढ़ गई होगी, लेकिन वह विषमता फैलाती है। मैं चाहती हूं कि सरकार की निगाह उन रेहड़ी वालों के ऊपर, फेरी वालों के ऊपर, छाबड़ी वालों के ऊपर भी जाए जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पांव और अपना गला एक साथ थकाते हैं। मैं देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या उनकी आमदनी में एक रुपए का भी इजाफा हुआ है? बल्कि उनके पास जो कुछ बचा खुचा था, वह भी महंगाई की भेंट चढ़ गया है। आप दूसरा तर्क देते हैं कि हमने किसानों को ज्यादा दाम देने शुरू कर दिए हैं इसलिए महंगाई बढ़ी है।, महाराष्ट्र में कपास का किसान आत्महत्या कर रहा है। आंध्र प्रदेश का किसान 'क्रॉप हालिडे' की घोषणा कर रहा है। पूरे देश में धन का किसान गैर खरीदी को लेकर त्राहि–त्राहि कर रहा है।

हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हावर्ड और आक्सफोर्ड नहीं समझा सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को वह समझा सकता है, जो आम लोगों की बात करता है। फीसदी की भाषा में बात करने वाले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं और उसका समाधान भी नहीं दे सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जिन 'राइजिंग लैवल्स' की बात कह रहे हैं, यह ठीक है कि कुछ लोगों की 'इनकम' इतनी 'राइज' हुई है कि वे दो हजार रुपए प्रति प्लेट पांच सितारा होटलों में खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपकी निगाह उन रेहड़ी वालों के ऊपर, फेरी वालों के ऊपर, छाबड़ी वालों के ऊपर भी जाए, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पांव और अगला गला एक साथ थकाते हैं। मैं देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या उनकी आमदनी में एक रुपए का भी इजाफा हुआ है? मैं इसीलिए आपसे कहना चाहती हूं कि आप बार–बार जो यह 'फ्रेज' इस्तेमाल करते हैं कि ''विद राइजिंग लैवल्स आफ इनकम'' यह किनकी आमदनी बढ़ी है, आप जरा उनकी तरफ भी निगाह डालिए, जिनकी आमदनी में एक रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। आप दूसरा तर्क देते हैं कि हमने किसानों को ज्यादा दाम देने

शुरू कर दिए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ी है। महाराष्ट्र में कपास का किसान आत्महत्या कर रहा है। आंध्र का किसान 'क्रॉप हालिडे' की घोषणा कर रहा है। पूरे देश का किसान त्राहि–त्राहि कर रहा है। मेरे गृह प्रदेश हरियाणा में बासमती का किसान सिर पकड़ कर रो रहा है। किसान 'क्राप होली डे' कर रहे हैं क्योंकि खाद्यान्नों की कीमत इतनी अधिक हो गई है कि यदि वे फसल उगाएंगे तो उसकी लागत फसल के विक्रय मूल्य से अधिक आती है आप कहते हैं कि आपने किसानों को ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया, इसलिए महंगाई बढ़ गई। किसान बेचता तो एक चीज है, बाकी सारी चीजों तो खरीदता है। लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं है। आप बड़े विदेशी पूंजी निवेश की बात करते हैं। ये जिन रेड़ी, फेरी और छावड़ी वालों की मैंने बात कही है, आपके यहां अगर यह एफडीआई खुदरा व्यापार में आ गई तो इनके तो केवल रोजगार ही तबाह नहीं होंगे बल्कि इनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। अभी जब से यह निर्णय लंबित हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म होने वाला था। आपने क्यों रूकवा दिया? रिफॉर्म वह होता है जिससे देश के लोगों की जिंदगी सुधरे। रिफॉर्म वह नहीं हो तो जिससे अमेरिका में इमेज सुधरे। अंतर्राष्ट्रीय जगत में छवि सुधरने से रिफॉर्म नहीं होता। रिफॉर्म तब होगा जब इन रेड़ी, फेरी और छावड़ी वालों की गुल्लक में चार पैसे डालेंगे। आप तीसरा तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ गए। अंतर्राष्ट्रीय दाम पेट्रोल के बढ़े तो समझ में आती है कि यहां दाम बढ़ गए लेकिन बाकी किस चीज के दाम अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ते हैं जिसका यहां असर पड़ता है। कभी उस मध्यमवर्गीय महिला के लिए सोचा है जिसकी रसोई में जिन चीजों को वह बनाती है, उसमें आग लग गई है और जिन चीजों पर वे पकाती है, उसकी आगे बुझ गई। खाना बनाने वाली चीजों में आग लगी पड़ी है और खाना बनाने वाली चीजों में आग बुझी पड़ी है। लेकिन ये जो आपके तर्क हैं, ये तर्क नहीं हैं, ये कुतर्क हैं। सच्चाई यह है कि महंगाई बढ़ी है आपकी गलत नीतियों के कारण, महंगाई बढ़ी है सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण। जहां तक नीतियों का सवाल है, यह आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि रुपए का इतना ज्यादा अवमूल्यन हुआ है। आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि बाजार से आपको 53 हजार करोड़ रुपए का ऋण लेना पड़ रहा है आपकी गलत नीतियों का परिणाम है कि 24 बार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। आप की गलत नीतियों का परिणाम है कि आरबीआई को 13 बार ब्याज की दरें बढ़ानी पड़ती हैं। जहां तक ब्याज दरों का सवाल है, आपको मालूम है कि जब ब्याज दर बढ़ती है तो औद्योगिक विकास भी बाधित होता है और हाउसिंग सेक्टर तो मर ही जाता है। जब कोई भी अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त होती है तो दो चीजें उसे उबारती हैं–हाउसिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। क्योंकि उसमें चौतरफा गतिविधि होती है।

हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को हावर्ड और आक्सफोर्ड नहीं समझा सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को वह समझा सकता है, जो आम लोगों की बात करता है। फीसदी की भाषा में बात करने वाले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं और उसका समाधान भी नहीं दे सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आप जिन राइजिंग लैवल्स की बात कह रहे हैं, यह ठीक है कि कुछ लोगों की इनकम इतनी राइज हुई है कि वे दो हजार रुपए प्रति प्लेट पांच सितारा होटलों में खाना खा सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आपकी निगाह उन रेहड़ी वालों के ऊपर, फेरी वालों के ऊपर, छाबड़ी वालों के ऊपर भी जाए, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने दोनों हाथ, अपने दोनों पांव और अगला गला एक साथ थकाते हैं। मैं देश के वित्त मंत्री से पूछना चाहती हूं कि क्या उनकी आमदनी में एक रुपए का भी इजाफा हुआ है?

आपके यहां निर्माण कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की यह हालत है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे यहां इतनी तेज गति से चल रहे थे, वे राजमार्ग नए तो क्या बनने थे, पुराने भी इतनी खस्ता हालत में हैं कि उनकी मरम्मत तक नहीं हो पा रही है और आज तो हम अखबार पढ़कर चौंक गए कि राष्ट्रीय राजमार्ग के सारे चीफ इंजीनियरों ने आज सामूहिक इस्तीफा दे दिया।

मैं आपसे कहना चाहती हूं कि यदि आप विदेशों में जमा कालाधन कल वापस ले आयें और सरकारी खजाने को लूटने से बचा लें तो कल ही महंगाई खत्म हो जाएगी। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपके जो हताशा भरे बयान आए, यह हताशा और निराशा 121 करोड़ का देश नहीं सह सकता है, नहीं सुन सकता है। अगर उन्होंने आपको सत्ता सौंपी है तो आप ही रास्ता निकालिए। क्योंकि आपको काम करना है इसीलिए शासन ने आपको उधर बैठाया है और हम इधर बैठे हैं। हम तो जनता के प्रहरी हैं, इसलिए हम तो जनता की बात कहेंगे। ■

एफडीआई से होगी उद्योग और कृषि व्यवस्था चौपट : अरुण जेटली

गत 12 दिसम्बर 2011 को राज्य सभा में अनुपूरक अनुदान मांगों पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली ने यूपीए सरकार की जन विरोधी नीतियों पर प्रहार करते हुए कहा कि गत 20 वर्षों में यह शायद झेली जा रही सर्वाधिक गंभीर स्थिति है। आज, समग्र स्थिति शोचनीय है। खाद्य मुद्रास्फीति कभी–कभी लगभग 20 प्रतिशत रही है। हम यहां उनके द्वारा दिये गये भाषण का सारांश प्रकाशित कर रहे हैं :–

एक ननीय वित्त मंत्री ने कुछ अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव किया है। मैं वित्तमंत्री से उनके द्वारा उठाए गए कुछ संगत मुद्दों के संबंध में आंशिक रूप से सहमत हूं। विश्व ने सबप्राइम संकट और यूरोजोन संकट के पश्चात आर्थिक मंदी को झेला है। तेल मूल्य वृद्धि ने भी गंभीर चुनौती प्रस्तुत की है। हमने एक दशक पूर्व एशियाई संकट को उचित तरीके से प्रभावी रूप से निपटा है। मेरा विचार है कि गत 20 वर्षों में यह शायद झेली जा रही सर्वाधिक गंभीर स्थिति है। आज, समग्र स्थिति शोचनीय है।

खाद्य मुद्रास्फीति कभी–कभी लगभग 20 प्रतिशत रही है। मुद्रास्फीति प्रायः लगभग 10 प्रतिशत के आस–पास रही है। जब तेल के मूल्य में वृद्धि होती है तो कच्चे तेल की लागत बढ़ जाती है, करों में भी वृद्धि हो जाती है। अवसंरचना में कुछ मंदी आई है। राजकोषीय घाटा अनुमानित आंकड़ों से कहीं अधिक होगा। इस वर्ष ब्याज दरों में चार बार वृद्धि की गई है। इससे भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। पूंजी की लागत में वृद्धि होती है तो इससे उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी। पूंजी की लागत में वृद्धि होती है ता इससे उद्योग गैर प्रतिस्पर्धात्मक हो जाता है। हमारा समग्र विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित होने जा रहा है। आवास संबंध ऋण महंगे हो गये हैं। जहां तक आर्थिक नीति संबंधी निर्णयों का संबंध है, निर्णय करने की प्रक्रिया में अचानक कमी आई है।

मेरा विचार है कि गत 20 वर्षों में यह शायद झेली जा रही सर्वाधिक गंभीर स्थिति है। आज, समग्र स्थिति शोचनीय है। खाद्य मुद्रास्फीति कभी–कभी लगभग 20 प्रतिशत रही है। मुद्रास्फीति प्रायः लगभग 10 प्रतिशत के आस–पास रही है। जब तेल के मूल्य में वृद्धि होती है तो कच्चे तेल की लागत बढ़ जाती है, करों में भी वृद्धि हो जाती है। अवसंरचना में कुछ मंदी आई है। राजकोषीय घाटा अनुमानित आंकड़ों से कहीं अधिक होगा। इस वर्ष ब्याज दरों में चार बार वृद्धि की गई है। इससे भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होगी।

भ्रष्टाचार से परियोजना की लागत बढ़ जाती है। पिछले 2 वर्षों में हमने यह देखा है कि भारत में एफडीआई के प्रवाह में न केवल ह्रास आ रहा है, बल्कि हमारे स्वयं के घरेलू व्यापारिक घराने अब विदेशी बाजारों में निवेश कर रहे हैं। आरंभ में हमने इसे एक उत्साहजनक दिखावटी प्रतिक्रिया के रूप में स्वीकार कर लिया था कि हमारे अपने कारपोरेट घराने बहुत बड़े हो गए हैं और वे अब विश्व कंपनियों का चयन कर रहे हैं। किन्तु, उन्हें यह पता चल

रहा है कि इन परिस्थितियों में भारत निवेश का उत्तम गन्तव्य नहीं है– यह चिंता का गंभीर कारण है।

वर्तमान शासन के मॉडल में एक बहुत गंभीर खामी है। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि सरकार के किसी भी कार्यक्रम को लागू करने के लिए तीन तत्व– नेतृत्व, सरकार की विश्वसनीयता और सरकार की शक्ति का वातावरण आवश्यक होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से संप्रग–II जब से सत्ता में आया है, हमने यह देखा है कि उनका दोहरा नेतृत्व कई मामलों में सहमत प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपके स्वयं के घटक दल खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का उग्रतापूर्वक विरोध कर रहे थे। इसलिए, जब कभी भी आप अपनी नीतियों की घोषणा करें, तो पहले संप्रग में आपस में पूर्ण सहमति बना लें। इसके बाद यदि आपको कोई दिक्कत आती है, तो आपको यह महसूस होगा कि यह निर्णय लागू नहीं किया जा सकता।

वर्तमान शासन के मॉडल में एक बहुत गंभीर खामी है। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि सरकार के किसी भी कार्यक्रम को लागू करने के लिए तीन तत्व– नेतृत्व, सरकार की विश्वसनीयता और सरकार की शक्ति का वातावरण आवश्यक होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से संप्रग–II जब से सत्ता में आया है, हमने यह देखा है कि उनका दोहरा नेतृत्व कई मामलों में सहमत प्रतीत होता हुआ नहीं दिख रहा है। आपके स्वयं के घटक दल खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का उग्रतापूर्वक विरोध कर रहे थे। इसलिए, जब कभी भी आप अपनी नीतियों की घोषणा करें, तो पहले संप्रग में आपस में पूर्ण सहमति बना लें। इसके बाद यदि आपको कोई दिक्कत आती है, तो आपको यह महसूस होगा कि यह निर्णय लागू नहीं किया जा सकता।

मैं आपको कुछ कारण बताता हूं। जब आप उनको कुछ बड़ी व्यापारिक रियायतें देते हैं, तो बदले में आपको भी कुछ रियायतें मिलती हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि क्यों उन्हें एकतरफा रूप से रियायतें प्रदान कर दी गयीं। आपको अत्यधिक सस्ते विनिर्माण का केन्द्र भी बनाना होगा। वैश्विक अनुभव यह दर्शाता है कि बड़े पैमाने पर खुदरा क्षेत्र में भी अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार से अतिरिक्त बाजारों का निर्माण नहीं होता है।

यह विद्यमान बाजारों को विस्थापित कर देते हैं। स्वरोजगार का सबसे बड़ा वर्ग कृषि क्षेत्र में आता है। उसके बाद खुदरा बाजार आता है। हम केवल उन्हें क्षेत्रों में सुधार करेंगे, जहां पर हमें सुधार करना है और जिसके फायदे भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेंगे। विश्व में कहीं पर भी अवसंरचनात्मक खुदरा व्यापार का सर्वोत्तम उदाहरण भारत का दुग्ध वितरण का उदाहरण है। भारत में एक दुग्ध उत्पादक को राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 70 प्रतिशत प्राप्त होता है। जबकि सहकारी क्षेत्र में उसे उपभोक्ता द्वारा चुकाये गए कुल रूपयों का 80 प्रतिशत मिल जाता है। जब हम सरकार में थे, तब आपके दल ने एफडीआई को राष्ट्र–विरोधी बताया था। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर एक विवि सम्मत बहस होनी चाहिए।

लोग कच्चे माल का आयात नहीं कर रहे हैं और इसलिए, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आ रही है। यदि आज देश की पूंजीगत वस्तुओं और विनिर्माण वस्तुओं के अंतःप्रवाह में गिरावट आ जाती है, तो अगले छह माह में औद्योगिक उत्पादन में कमी आ जाएगी। धन की कमी की बात करके, आपने 13 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी जिससे पूंजी बहुत महंगी हो गई।

जब तक हम इसमें कमी नहीं लाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था की गति धीमी बनी रहेगी। वित्तीय घाटा 4.6 प्रतिशत है जो 5 प्रतिशत के पार भी जा सकता है। जब लोग भारत में डॉलरों में निवेश नहीं कर रहे हैं, तो भारतीय इस देश में क्यों रूपयों में निवेश करेंगे? वे भी आकर्षक बाजारों की खोज करेंगे। इसके अलावा, आपको कांग्रेस दल शासित राज्यों और गैर–कांग्रेसी दल शासित राज्यों में संसाधनों के आवंटन और अन्य प्रशासनिक मामलों में फर्क नहीं करना चाहिए।

आपको एक नेतृत्व वाली, विश्वसनीयता वाली सरकार की आवश्यकता है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर व्यक्तिगत रूप से कोई संदेह नहीं है। वह एक ईमानदारी व्यक्ति हैं, परन्तु, सरकार को साख की जरूरत है। इसे हासिल करने के लिए उसे नेतृत्व की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत हों। राजनीतिक शक्ति उनके पास होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुख्य कार्यपालक हैं। इसलिए उन्हें प्रभुत्व के साथ कार्य करना चाहिए। तभी हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं। ■

जनता रो रही है और सरकार सो रही है - वेंकैया नायडू

राज्यसभा में 7 दिसम्बर 2011 को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एम. वेंकैया नायडू ने बढ़ती महंगाई के कारण जनता की परेशानियों का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर जनता रो रही है वहीं दूसरी ओर सरकार सो रही है। हम उनके भाषण का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं :–

क्या यह हमारे लिए कृषक समुदाय की समस्याओं को हल करने और स्थिति में सुधार करने का समय नहीं है? यदि आप कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं, यदि आपके पास कोई नए विचार नहीं हैं, यदि आप विचारों के संबंध में राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, तो बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दें और इसके बाद, लोगों को निर्णय लेने दीजिए।

मूल्य–वृद्धि एक धीमा जहर है। यह आम आदमी पर प्रहार है। फरवरी, 2010 में माननीय वित्तमंत्री ने वादा किया था कि अत्यधिक महंगाई में चार माह के भीतर कमी आएगी। परन्तु, कुछ नहीं हुआ। वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। कोई उपाय नहीं है। सरकार ने वित्तीय, आर्थिक और बाजार बाजार हस्तक्षेप जैसे उपाय किए हैं, परन्तु वे सभी विफल रहे हैं। दूरदृष्टि, समुचित योजना, नेतृत्व का अभाव और सबसे बढ़ कर अत्यधिक अक्षमता, गलत आर्थिक नीतियां, आयात और निर्यात में व्यापक भ्रष्टाचार मूल्य–वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। ऐसा सरकार के कुप्रबंधन और गलत आर्थिक नीतियों के कारण हो रहा है। मुद्रास्फीति के कारण मसाले, अंडे, मछली, मांस, दूध और दालें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। यदि वृद्धि कम हो, तो मुद्रास्फीति स्वीकार्य है। परन्तु, वृद्धि–दर भी कम हो रही है। सभी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। ब्याज दरों, ईंधन की कीमतों, उर्वरक की कीमतों, ईएमआई में बढ़ोतरी के कारण आम आदमी का बजट दुःस्वप्न में बदल रहा है। गरीबी उपशमन के उपाय करने के बजाय, सरकार ने सोचा कि एक व्यक्ति की दैनिक आमदनी 23 रूपए प्रतिदिन तय करके वह गरीबी कम कर सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति 23 रूपये प्रतिदिन से गुजारा कर सकता है?

यहां तक कि रूपये का मूल्य भी घट रहा है। यह अब तक के सबसे कम मूल्य पर आ गया है। श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? इसमें 64 विस्तृत कार्रवाई योग्य बिन्दुओं के साथ 20 सिफारिशें की गई हैं। यह सिफारिश की गई है कि सभी आवश्यक वस्तुओं को वायदा बाजार से अलग रखा जाना चाहिए। एक मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना, कृषि बाजारों का पुनर्वास, प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों में विस्तार, सभी स्तरों पर सूचना का प्रसार, ये कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं।

सरकार लोगों को यह स्पष्ट करने में विफल रही है कि उसने इस प्रतिवेदन पर क्या कार्रवाई की है। पेट्रोल की कीमतों को तर्कसंगत बनाए जाने के नाम पर बारह महीने में इसमें ग्यारह बार बढ़ोतरी की गई है। इसका आवश्यक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। मूल्य–वृद्धि अधिकतर खाद्य वस्तुओं में हो रही है। चीनी, चावल, इस्पात, कोयला, तेल, दाल इत्यादि सभी वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। यदि आप खाद्यस्फीति के लिए कम उत्पादन को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो यह सही नहीं है क्योंकि रिकार्ड उत्पादन हुआ है। परन्तु, गत साढ़े छह वर्षों में भंडारण क्षमता में एक मीट्रिक टन की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य में नाम मात्र की बढ़ोतरी कर रहे हैं। परन्तु, इसके साथ–साथ, कृषि आदानों की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हो रही है। किसान खेती–बाड़ी करना छोड़ रहे हैं। तैंतालीस प्रतिशत कृषक समुदाय खेती–बाड़ी छोड़ना चाहता है, क्योंकि यह लाभकारी नहीं है।

क्या यह हमारे लिए कृषक समुदाय की समस्याओं को हल करने और स्थिति में सुधार करने का समय नहीं है? यदि आप कीमतों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं, यदि आपके पास कोई नए विचार नहीं हैं, यदि आप विचारों के संबंध में राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, तो बेहतर है कि आप इस्तीफा दे दें और इसके बाद, लोगों को निर्णय लेने दीजिए।■

पैसा देकर मौत को निमंत्रण देने का नाम बन गया है रेलवे : प्रभात झा

गत 22 दिसम्बर 2011 को राज्यसभा में ''विनियोग रेल (संख्यांक 3) विधेयक, 2011 और रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) संशोधन विधेयक, 2008'' विषय पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा सांसद श्री प्रभात झा द्वारा दिए गए भाषण का संक्षिप्त पाठ–

Hkkरतीय रेल एक समय में भारत के परिवहन दृष्टि से बहुत सुविधाजनक हुआ करता था और लोग उसमें शौकिया सफर करते थे। भारत देश विश्व का बहुत बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में दो करोड़ लोग 11 हजार रेल में रोज सफर करते हैं तथा 1,739 लाख टन माल की ढुलाई होती है।

एक दशक से अधिक तक रेलवे, भारत सरकार को अपने राजस्व का लाभांश दिया करता था, लेकिन आज उसकी स्थिति यह हो गई है कि 2011–12 में वित्तीय संकट इतना है कि 2007–08 में रेलवे के पास 19 हजार करोड़ रुपये थे और इसका अतिरिक्त लाभ कोष था, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा 2010 में खर्च हुआ और रेलवे के पास 5 हजार करोड़ का अधिकोष बचा था। लेकिन पूरे सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सितम्बर, 2011 तक रेलवे के पास नकद अधिकोष मात्र 75 लाख रुपये बचा हुआ है। कहां 19 हजार करोड़ का अधिकोष और कहां 75 लाख रुपये? इस तरह रेलवे का स्वास्थ्य पूरी तरह से संकट में है। इसका एक परिचालन अनुपात होता है, जिससे रेलवे में क्या हुआ, कितना आगे बढ़ा, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। परिचालन अनुपात से अभिप्राय है कि रेलवे को सौ रुपये कमाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है। 2008–09 में सौ रुपये कमाने के लिए रेलवे 90.

5 रुपये खर्च करती थी। 2009–10 में 94.7 रुपये खर्च करती थी, लेकिन 2010–11 आते–आते भारतीय रेल सौ रुपये कमाने के लिए 125 रुपये खर्च करता है। भारतीय रेल की क्या हालत है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है। 2007–08 में रेलवे की परिचालन लागत 41 हजार 33 करोड़ थी, जो 2011–12 में बजट का सिर्फ दोगुना 73 हजार 650 करोड़ रुपये पहुंच गई। इस अवधि में मात्र पेंशन आठ हजार करोड़ रुपये थी, अब वह 16 हजार करोड़ तक पहुंच गई है। हालत यह है कि आधुनिकीकरण के नाम पर सारी योजनाएं कागजों पर है।

आपने मात्र दिल्ली डिविजन के रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी ही घोषणाएं की थीं। माननीय मंत्री जी, 240 करोड़ रुपये की योजना आपके पास थी, लेकिन धन के अभाव में सात हजार रेलवे स्टेशन आपका मुंह देख रहे हैं कि जो 2011–12 में बजट की घोषणा की थी, वह कब पूरी होगी? यह सब कैसे होगा?

यह कैसे होगा? 75 लाख रुपये नगद अधिकोष आपके पास है और देश के लगभग 7 हजार से अधिक स्टेशन आज भी प्रगति के लिए आपका मुंह देख रहे हैं। भारतीय रेल के करीब 13. 61 लाख रेल कर्मचारियों को वेतन बांटना है। आपकी क्या हालत हो रही है? आप 2000 करोड़ रूपए मांग रहे हैं, कैसे देंगे आप, कैसे बांटेंगे? और आपको मजबूरी में पैसा लेना पड़ रहा है। 140 सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड (SAG) के अतिरिक्त ऐक्सेस अधिकारियों को घर बैठाकर, फर्जी ट्रेनिंग पर भेजकर, उन्हें वेतन दिया जा रहा है जिसमें करोड़ों रूपये आपके द्वारा फूंके जा रहे हैं। रेलवे के पास जितने स्वीकृत पद हैं, उससे अधिक लोगों को आपने प्रमोशन दे दिया है। रेलवे की वित्तीय स्थिति ऐसी हो गयी है कि काम करवा लेने के बाद, जो ठेकेदार काम करते हैं और जो ठेकेदार के लोग काम करते हैं, उन्हें देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। संसद की स्थायी समिति ने 2010–11 की बैठक में सवाल उठाये हैं, उन सवालों में कहा गया है कि रेलवे की डिब्बा और इंजन निर्माण में देरी सहित 11वीं पंचवर्षीय योजना का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। आपकी जो योजनाएं हैं, उनके लिए सारे सदस्य चिंताग्रस्त थे। आपने रेलवे द्वारा अनुसंधान में होने वाले खर्च में कटौती की, इससे जाहिर होता है कि आप रेलवे को कहां ले जा

रहे हैं? वर्ष 2010–11 में 78 करोड़ रुपये और अब उसको घटाकर 41 करोड़ रुपये कर दिया, ये आपके आंकड़े हैं, ये मेरे निजी या घर के आंकड़े नहीं हैं। आपने कहा कि आप मॉडल स्टेशन बनायेंगे। आपने कितने मॉडल बनाये हैं और क्या आप इनके बारे में हमें बतायेंगे? आपने कहा कि आप आधुनिक स्टेशन बनायेंगे, इनकी घोषणा करने में क्या लगता है, जुबान ही तो हिलानी है, हिला दी।

आपने कहा कि मल्टी फक्शनल काम्पलेक्स समेत यात्री सुविधाओं के लिए सब कुछ करेंगे। आप क्या–क्या कर रहे हैं? लगभग 9–10 महीने हो गए हैं, क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में देखिए। एक समय था जब पचास के दशक में रेलवे का शेयर 89 परसेंट हुआ करता था और रोड ट्रांसपोर्ट का शेयर 11 परसेंट हुआ करता था, लेकिन अब ठीक उल्टा हो गया है। वर्ष 2010–11 में जो कुल ट्रेफिक है, उसमें रेलवे का हिस्सा 20 परसेंट है और रोड ट्रांसपोर्ट का हिस्सा 80 परसेंट है। अब यह हमारी रेलवे का हाल है।

सर, हम सब रेलवे में सफर करते हैं और बूढ़े पुलों की हालत क्या है? एक अधिकृत जानकारी के अनुसार देशभर में तकरीबन 1,27000 पुल हैं, जिनमें 51 हजार पुल 100 साल से पुराने हो चुके हैं, आप रेल में जिंदगी लेकर चलते हैं और जब इन पुलों पर से ट्रेन जाती है, तो हजारों लोगों की जिंदगी जा सकती है। क्या आपके पास इन पुलों को ठीक करने के लिए पैसा है? ये पुल अंग्रेजों के जमाने से चल रहे हैं, आप क्या करेंगे? इतना ही नहीं पटरियां गल रही हैं। तटीय स्थलों पर, समुद्र के पास की जितनी पटरियां है, 14000 किलोमीटर रेल की पटरियां गल रही हैं और जब उन पर से ट्रेन जायेगी और कोई हादसा होगा, तो रेल मंत्री जी, आप उस समय कहेंगे कि मुआवजा ले लो, नौकरी ले लो, ये ले लो, वह ले लो। इसमें बहुत सारे लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हें, सामान्य परिवार के लोग जाते हैं, इन गली हुई पटरियों को ठीक करने के लिए, आप 440 करोड़ रूपये कहां से लायेंगे? मैं बताना चाहता हूं कि ये पटरियां प्राकृतिक प्रकोप के कारण नहीं गल रही हैं। इन पटरियों के गलने के कुछ मानवीय दोष

एक दशक से अधिक तक रेलवे, भारत सरकार को अपने राजस्व का लाभांश दिया करता था, लेकिन आज उसकी स्थिति यह हो गई है कि 2011–12 में वित्तीय संकट इतना है कि 2007–08 में रेलवे के पास 19 हजार करोड़ रुपये थे और इसका अतिरिक्त लाभ कोष था, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा 2010 में खर्च हुआ और रेलवे के पास 5 हजार करोड़ का अधिकोष बचा था। लेकिन पूरे सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि सितम्बर, 2011 तक रेलवे के पास नकद अधिकोष मात्र 75 लाख रुपये बचा हुआ है। कहां 19 हजार करोड़ का अधिकोष और कहां 75 लाख रुपये? इस तरह रेलवे का स्वास्थ्य पूरी तरह से संकट में है।

भी हैं। इन पर मल–मूत्र गिरता है, इनका क्षरण होता है, लोहे को जंग लगती है, लेकिन यह सब देखेन के लिए आपके पास कोई समय नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि भारत के महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कमजोर पटरियों पर रेल चलाने से रेल मंत्रालय को 3200 करोड़ रूप्ये का नुकसान हो रहा है। एक दशक में एक हजार रेल गाड़ियां चला दीं, लेकिन कोच कोई ठीक–ठाक नहीं है। देश में इस समय 32,694 संपारित फाटक हैं, जिनमें 14,853 मानवरहित हैं। सिर्फ इस घटना ने 229 लोगों की जानें ली हैं।

मंत्री जी, आपने घोषणा की थी कि आगामी वित्त वर्ष में 120 ट्रेनें चलाएंगे। आप घोषणा कीजिए, लेकिन बताइए कि कितनी ट्रेनें चला रहे हैं? 117 नई ट्रेंने चलाई जाएंगी, रेलवे का निजीकरण नहीं हो ने दिया जाएगा, हर साल 1,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें बनाएंगे, पंचायत, जिला.... जरा, घोषणाएं तो देखिए, आप ऐसी घोषणाएं करते हैं कि वहां पर ई–गवर्नेंस हो जाएगा, ई–टिकट हो जाएगा, लेकिन जहां टिकट देना चाहिए, वहां तो टिकट मिल नहीं रहा है, धांधलियां हो रही हैं। राजस्व हासिल करने के लिए बिजनेस मॉडल बनाएं जाएंगे, पांच शहरों में स्पोर्ट्स अकादमियां बनाई जाएंगी, साफ और स्वच्छ पानी मुहैया कराया जाएगा, लेकिन स्टेशनों पर पानी की टंकियां नहीं दिख रही हैं, आप प्लास्टिक की टंकियां तक नहीं दे पा रहे हैं। आपने कहा निवेश बढ़ाने के लिए नीतियों पर जोर देंगे, आप दो–चार और ऐसी बातें बोल दीजिए। यह कहा गया कि पंचायत स्तर पर ई–टिकटिंग केंद्र होगा, अरे जहां है, कृपया करके वहां तो ठीक कर दीजिए। आपने कहा है कि तीन रेलवे जोंस में एंटी कोलोजियन उपकरण लगाएंगे। यह जो धुंध होती है, जिसमें रेल नहीं जा पाती है, आपने कहा था उसके लिए लगाएंगे, लेकिन क्या आपने लगा दिए? यह गाड़ी उल्टी चलने लगी। धुंध में गाड़ी को आगे चलना चाहिए, लेकिन वह पीछे चलने लगती है। पता नहीं, यह कौन सा रेल विभाग है। आज आदमी रेल में चढ़ते समय कंपकंपाता है, उसके पांव कांपते हैं कि चढ़ूं या नहीं चढ़ूं। पैसा देकर मौत को निमंत्रण देने का नाम है– रेल मंत्रालय। ■

सौ शरदों की वाणी मौन क्यों है?

'kkUrk d|ekj

eSa अटल जी के सामने खड़ा था। अटल जी बिस्तर पर लेटे हुए थे...कमजोर...बहुत कमजोर। तन की सीमाओं के बन्धन का एहसास उनकी वाणी को विराम दिए हुए था। रंजन ने उनके कान में मेरा नाम जोर से पुकारा। वह ध्यान से देखने लगे और देखते ही रहे। मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था... पर कह नहीं पाया। मेरा अन्तर बुझा–बुझा सा रहा। वाजपेयी जी का मौन अखर रहा था। उनकी एक कविता की पंक्तियां मेरे ज़ेहन में घूमने लगी :–

'पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी/जीवन एक अनंत कहानी/पर तन की अपनी सीमाएं/यद्यपि सौ शरदों की वाणी/इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलें/अपने ही मन से कुछ बोलें।'..... मुझे लगा वाजपेयी जी तन की अपनी सीमाओं को समझते हुए अपने ही मन से कुछ बोल रहे हैं. ....शायद तभी मौन हैं।

मेरी आंखों में एकदम लाखों हजारों की भीड़ के सामने मंच पर दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे करते हुए अपनी विशेष मुद्रा में भाषण देते हुए श्री अटल जी का चित्र उभर आया। उनका भाषण वर्षों तक लाखों श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध करता रहा। उनके भाषण के शब्दों की भाव–भंगिमा और आंखों की अभिव्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित होते ही लगता था कि दिल की धड़कनें रुकने लगी हैं और समय भी ठहर सा गया है। – वह प्रेरणा दायिनी ओजस्वी वाणी आज मौन हो गई है। वे मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। मेरी आंखें में अतीत की बहुत सी यादें एक–एक कर उभरने लगी।

1957–58 में मैं दिल्ली यमुना पर गांधी नगर डीएवी स्कूल में पढ़ाता था। प्रचारक रहे मेरे मित्र अध्यापक श्री सोम नाथ जी की शादी हुई। हम उनका स्वागत समारोह करना चाहते थे। श्री अटल जी को निमंत्रण देने उस समय के भारतीय जनसंघ के अजमेरी गेट कार्यालय में पहुंचा। तीसरी मंजिल पर एक छोटे से कमरे में श्री जगदीश माथुर और श्री अटल जी बैठे थे। श्री अटल जी ने एकदम निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विवाह के उपलक्ष में छोटा–सा स्वागत समारोह लगभग 50–60 लोग थे। अटल जी आये। उनके भाषण का यह वाक्य आज भी याद है – 'मुझे विवाह का कोई अनुभव नहीं परन्तु मैंने सुना है विवाह एक ऐसा स्थान है कि जो उसके बाहिर है वे अन्दर जाना चाहते है और जो अन्दर है वे बाहिर आना चाहते हैं।' पूरा वातावरण खिलखिलाहट से गूंज उठा था। आज सोचता हूं उस छोटे से कार्यक्रम में मेरे कहने पर वे अटल जी आ गये थे जो बाद में कितने ऊंचे स्थान पर पहुंचे। श्री अटल जी प्रारम्भ से ही सहज, सरल और स्वाभाविक प्रकृति के थे।

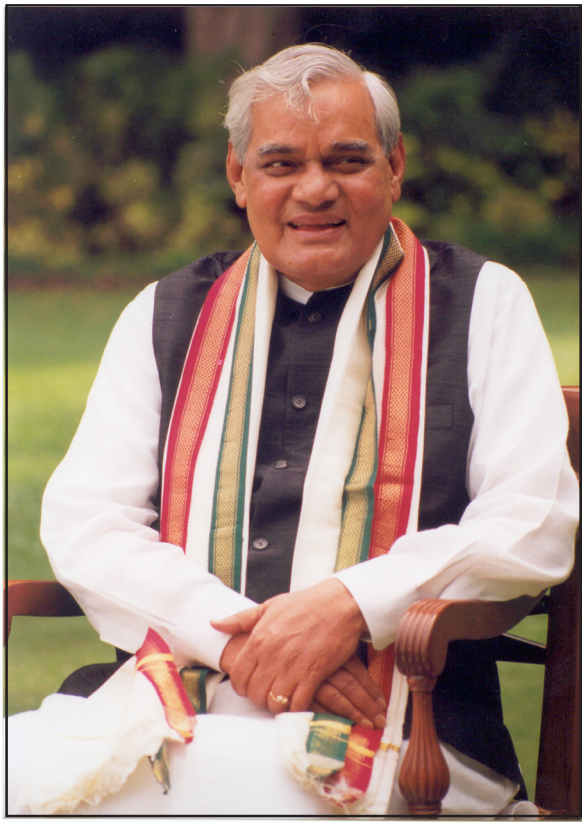

अटल जी हिमाचल के प्रवास पर थे। कुल्लु से पालमपुर की यात्रा में एक जगह बर्फ से ढके धौलाधार पर्वत को देखकर एकदम कह उठे ठहरो ! ठहरो! कार खड़ी की। बाहर निकले। श्वेत धवल धौलाधार को देखते रहे। कहने लगे – ' मैं विश्वभर में घूमता हूं परन्तु ऐसी समतल वादी से इतने ऊंचे बर्फ से ढके हुए पर्वत का इतना निकटस्थ दृश्य कभी कहीं देखने को नहीं मिला।' मेरे पालमपुर के घर में आकर भोजन और विश्राम किया परन्तु धौलाधार का दृश्य उनकी आंखों में

छाया रहा।

एक चुनाव में हम सब हार गये। अटल जी भी हार गये। मैं दिल्ली गया था। श्री कृष्ण लाल शर्मा जी के साथ अटल जी को मिलने गये। मैं और अटल जी बाहिर टहलने लगे। चलते–चलते अटल जी एकदम खड़े हो गये और अपने अन्दाज में दोनों हाथ घुमाकर कहने लगे – 'क्या हमने कभी सोचा था कि हम भी चुनाव हार जाएंगे।' मैंने पहली बार उनके चेहरे पर विषाद की रेखाएं देखी। हम घूम रहे थे। श्री कृष्ण लाल शर्मा जी आये और अटल जी से पूछने लगे कि मध्यप्रदेश वाले एक कार्यक्रम के लिए समय चाह रहे हैं। वे बार–बार पूछ रहे हैं। श्री अटल जी ने उसी अन्दाज में हाथ घुमाते हुए कहा –'नहीं–नहीं, बिल्कुल नहीं मुझे किसी कार्यक्रम में नहीं जाना है।' श्री कृष्ण लाल शर्मा जी वापिस चले गये। हम थोड़ी देर घुमते रहे। अटल जी के आग्रह पर हम भोजन के लिए बैठे, पूरा समय श्री अटल जी के मन की उदासी बार–बार अभिव्यक्त होती रही। भोजन करके हम चलने लगे तो कृष्ण लाल शर्मा जी ने फिर बड़े आग्रह से कहा 'कार्यक्रम महत्वपूर्ण है। प्रदेश वाले बार–बार आग्रह कर रहे हैं। आप मान जाएं।' श्री अटल जी ने फिर मना कर दिया। बाहिर निकलते हुए श्री कृष्ण लाल शर्मा ने थोड़े गुस्से से कहा – 'तो फिर मैं उन्हें मना कर दूं' अटल जी ने जोर से कहा 'हाँ'। शर्मा जी रूक गये और अपने हास्य अन्दाज में कहने लगे – 'अटल जी एक बात बतायें, शान्ता कुमार का तो अपना परिवार है छोटा सा व्यवसाय है। उन्हें और भी कई काम हैं। पर आप अगर कार्यक्रमों में नहीं जाएंगे तो और करेंगे भी क्या' सुनते ही श्री अटल जी जोर से हंस पड़े। हम सब भी उस हंसी में शामिल हो गये। सारी उदासी दूर हो गई। अटल जी बोले 'बिल्कुल ठीक है मैं और क्या करूंगा। मैं कार्यक्रम में जाऊंगा।' उनके व्यक्तित्व की सहजता और स्वाभाविकता एक बड़ी विशेषता थी। ऐसे मौकों पर उनकी उन्मुक्त हंसी से सारा वातावरण खिलखिला उठता था।

मेरी आंखों में एकदम लाखों हजारों की भीड़ के सामने मंच पर दायां हाथ ऊपर और बायां हाथ नीचे करते हुए अपनी विशेष मुद्रा में भाषण देते हुए श्री अटल जी का चित्र उभर आया। उनका भाषण वर्षों तक लाखों श्रोताओं को मन्त्र मुग्ध करता रहा। उनके भाषण के शब्दों की भाव–भंगिमा और आंखों की अभिव्यक्ति पर ध्यान केन्द्रित होते ही लगता था कि दिल की धड़कनें रुकने लगी हैं और समय भी ठहर सा गया है। – वह प्रेरणा दायिनी ओजस्वी वाणी आज मौन हो गई है। वे मुझे देख रहे थे और मैं उन्हें देख रहा था। मेरी आंखें में अतीत की बहुत सी यादें एक–एक कर उभरने लगी।

दिल्ली के एक नेता सुभाष आर्य के घर में शादी थी। खूब भीड़ भी थी। मैं श्री कृष्ण लाल शर्मा जी के साथ खड़ा था। किसी ने हमें भोजन के लिए आमंत्रित किया। हम सब उस तरफ बढ़े। श्री अटल जी भी पास में खड़े थे। भीड़ बहुत अधिक थी। कोई अलग व्यवस्था नहीं थी। श्री अटल जी ने श्री शर्मा जी के साथ बात की और बाहिर निकलने को कहा। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। भोजन किये बिना गाड़ियों में बैठ कर चल दिये। श्री कृष्ण लाल शर्मा जी ने कहा भोजन तो घर में भी नहीं बना होगा, कहीं खाकर चलते हैं। श्री कृष्ण लाल शर्मा जी बहुत मस्त स्वभाव के थे। नये–नये स्थान पर भोजन करना उन्हें अच्छा लगता था। मेरे साथ उनका बहुत स्नेह और प्यार था। मैं जब भी दिल्ली जाता था वे मुझे लेकर किसी नये रेस्टोरेंट में भोजन कराते थे। कनॉट प्लेस के एक नये रेस्टोरेंट के सामने शर्मा जी ने गाड़ी रोकी। हम तीनों रेस्टोरेंट में जा कर बैठ गये। एक सुन्दर स्मार्ट महिला फर्राटे से अंग्रेजी बोलती हुई बात करने लगी। हमने हिन्दी में कुछ पूछा। महिला फिर कहने लगी 'यहां बिल्कुल घर की तरह खाना मिलता है।' श्री कृष्ण लाल शर्मा जी ने मेन्यु को ध्यान से पढ़ा और पूछने लगे क्या सचमुच यहां घर की तरह खाना मिलता है। महिला ने बड़े विश्वास से सहमति पकट की। तब कृष्ण लाल शर्मा जी ने अपने अन्दाज में कहा – 'घर के खाने से दुखी होकर ही तो यहां आये हैं। यहां भी वही.....'– अटल जी उन्मुक्त हंसी हंसने लगे, ठहाके गूंजे। उसके बाद हमने भोजन किया। श्री कृष्ण लाल शर्मा जी के साथ हास्य–विनोद साथ–साथ रहता था। बात–बात पर चुटकले सुनाते थे। उनके साथ रह कर वातावरण कभी गंभीर नहीं होता था।

एक बार अटल जी सोलन में आये। बहुत प्रयत्न करके उन्हें 11 हजार रूपये की थैली भेंट की। कार्यक्रम के बाद चाय पी रहे थे। एक कार्यकर्त्ता ने कहा 'आपका भाषण बहुत ओजस्वी था पर बहुत छोटा था।' श्री अटल जी अपने अन्दाज में कह उठे– 'सिर्फ 11 हजार रूपये में कितना भाषण किया जा सकता था।' पूरा वातावरण हंसी में गूंज उठा।

6 दिसम्बर को अयोध्या का ढांचा गिरने के एकदम बाद अटल जी शिमला आये थे। चर्चा चली तो कहने लगे –

'ऐसी कोई योजना थी तो हमें भी बताया होता....कुछ पता ही नहीं था जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ।' मैंने अटल जी को याद दिलाया राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में मैंने कहा था कि अयोध्या में लाखों लोग इकट्ठे होंगे तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। उस समय के हम चार मुख्यमंत्रियों श्री भैरों सिंह शेखावत, कल्याण सिंह व सुन्दरलाल पटवा ने एक दिन पूर्व विस्तार से यह तय किया था कि हम 6 दिसम्बर को टालने का आग्रह करेंगे। अटल जी ने कहा– 'आपने कहा था पर किसी ने सुना नहीं' मुझे याद है अटल जी इस सारी घटना से बहुत व्यथित थे।

मंत्रिमण्डल में लोकपाल बिल के मसौदे पर चर्चा हो रही थी। प्रधानमंत्री पद को लोकपाल के दायरे में रखने पर ज्यों ही चर्चा शुरू हुई तो अटल जी एकदम बीच में बोल पड़े – 'चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं प्रधानमंत्री का पद लोकपाल के जांच दायरे में अवश्य रहेगा।' अटल जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मुझे खाद्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया। खाद्य मंत्री बनने के कुछ दिन बाद मेरे ध्यान में सैंपल सर्वे की वह रिपोर्ट लाई गई जिसमें कहा गया था कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे गरीबों की संख्या 28 करोड़ है परन्तु पांच करोड़ लोग इतने गरीब हैं कि लगभग भूखे ही रहते हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट का अध्ययन किया। उन दिनों मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। अनाज बाहर रखा था, वर्षा पड़ती थी, अनाज खराब होता था।

कुछ दिन के बाद उड़ीसा के काली हांडी से भूख से मरने वालों का समाचार मिला। प्रैस में और लोकसभा में हमारी सरकार की आलोचना हुई। एक हिन्दी समाचार पत्र ने कालाहांडी में कुपोषण और भुखमरी का ऐसा वर्णन किया था कि रात को मैं ठीक से खाना नहीं खा सका। दूसरी प्रातः मैं अटल जी को मिलने गया। सारी परिस्थिति उनके सामने रखी। समाचार–पत्र का समाचार भी पढ़ाया। मैंने भावुकता से कहा –'मुझे अपना आप अपराधी लग रहा है। आप प्रधानमंत्री है। मैं खाद्य मंत्री हूं। अनाज से गोदाम भरे पड़े हैं। रखने की जगह नहीं और पांच करोड़ लोग रात को भूखे पेट सोते हैं।' अटल जी मेरी और देखने लगे। कुछ देर हम दोनों चुप रहे। आज भी मुझे उनकी आंखों में संवेदना की तरलता नजर आ रही है। अपने विशेष अन्दाज में मुझे कहा 'तो फिर कुछ करो ?' मैं बिल्कुल तैयार था– अन्त्योदय अन्न योजना की पूरी जानकारी उन्हें दी। उन्होंने कहा 'पूरी योजना को एकदम मंत्रिमंडल में ले आओ।'

वित्तीय कठिनाईयों के कारण मंत्रिमंडल में मेरा सुझाव स्वीकार नहीं हुआ। मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में भी मेरे आग्रह को स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्ताव श्री आडवाणी जी की अध्यक्षता में एक मंत्रीसमूह को दिया गया। मेरे आग्रह पर प्रस्ताव स्वीकार कर मंत्रिमंडल में आया। परन्तु वित्तीय कठिनाईयों के कारण फिर स्वीकार नहीं हो पाया।

मैं बहुत व्यथित था। भुखमरी के समाचार आते थे और अन्न भण्डार लबालब भरे थे। 25 दिसम्बर को अटल जी के जन्म दिन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्घाटन होने वाला था। तीन या चार दिन पहले फिर कालाहांडी का एक समाचार पढ़ा। पता नहीं क्या सोचकर मैं तुरन्त अटल जी से मिलने चला गया। समाचार पत्र उनके समक्ष रखा और मन की पूरी व्यथा व्यक्त की। कुछ देर हम दोनों चुप रहे फिर मैंने कहा 'क्या ही अच्छा हो यदि 25 दिसम्बर आपके जन्म दिन पर ग्राम सड़क योजना के साथ अन्त्योदय अन्न योजना का भी उद्घाटन हो जाए।' अटल जी कुछ देर मुझे देखते रहे फिर अपने स्वभाविक अन्दाज में हाथ घूमा कर बड़े आग्रह से कहा 'ठीक है– शुरू कर दो पर मंत्रिमण्डल में....' कहकर वे कुछ सोचने लगे। मैं पूरी तैयारी करके गया था। मैंने कहा 'मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना भी आपको योजना प्रारम्भ करने का विशेष अधिकार है – बस एक काम कर दीजिए, वित्तमंत्री को कह दीजिए।' मैं पूरी तरह से तैयार था। योजना का पूरा प्रारूप एकदम सभी प्रदेशों को भेजा और 25 दिसम्बर को योजना प्रारम्भ हो गयी। शायद यह पहली ऐसी योजना होगी जो मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना प्रारम्भ हुई हो। स्वीकृति कई महीनों के बाद मिली।

अटली जी का कवि हृदय संवेदना से ओतप्रोत था। आज भी इस योजना में लगभग 10 करोड़ अति गरीब लोगों को कमर तोड़ मंहगाई में 35 किलो अनाज, 2 रूपये किलो गेंहू और 3 रूपये किलो चावल के हिसाब से मिलता है। यह विश्व की गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी योजना है।

अटल जी एक व्यक्ति नहीं संस्था है। वे आधुनिक भारत के राजनैतिक इतिहास का एक गौरवशाली महत्वपूर्ण अध्याय हैं। पार्टी को 'क्लास से मास' बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। बहुमुखी प्रतिभा के एक अद्वितीय नेता हैं। केन्द्र में पहली बार एक सफल गैर कांग्रेस सरकार चलाने का गौरव उन्हें प्राप्त है।

अटल जी को मिलकर घर लौटा तो अतीत की कितनी ही स्मृतियों की बरसात में भीगा हुआ था। पिछले लगभग पचास वर्षों से उनका संपर्क स्नेह मार्ग दर्शन लेकर चलता रहा था। रह–रह कर एक ही बात मन से निकल रही थी – काश वे स्वस्थ होकर हमारा मार्ग–दर्शन करते रहें। ■

इरादों के पक्के हैं नितिनजी

✍ ÇHkkr >k

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी की सरलता इसी बात से आंकी जा सकती है कि वो स्वयं कहते हैं कि आज से 20–25 साल पहले मैं पार्टी का पोस्टर चिपकाता था, दीवार लेखन करता था और ऑटो में बैठकर पार्टी का प्रचार करता था। आगे वो कहते हैं कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व देगा। इस तरह की सच्चाई, बेबाकी से कहने का सामर्थ्य सामान्य व्यक्ति में नहीं होता है। नितिनजी की यह खासियत है कि वे जहां से चले थे उसे सदैव स्मरित रखते हैं और जहां जाना है उसकी चिंता संगठन पर छोड़ देते हैं। दिल्ली उन्हें आज भी नहीं भा रही इसलिए वे सप्ताह में एक या दो दिन नागपुर पहुंच ही जाते हैं। दिल्ली में लड़ने की ऊर्जा उन्हें दिल्ली से अधिक नागपुर से प्राप्त होती है। विदर्भ की प्रकृति अलग है। वहां के लोग 'बिन्दास' होते हैं। वहां के लोग हंसते–खेलते सभी काम करते हैं। यही कारण है कि नितिनजी की कार्यशैली में तनाव का कोई स्थान नहीं है। उनका स्वभाव परिणामकारी है। वे परिणाम के प्रति परिणामयुक्त कर्त्तव्य की अपेक्षा करते हैं। उनका मानना है कि संगठन में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जिसके लिए कोई काम न हो। अभी तक जिन्होंने भी उनसे दिल से काम मांगा उन्होंने सहर्ष दायित्व सौंपा। वे चाहते हैं कि कार्यकर्ता मुस्कुराता रहे। उनकी मान्यता है कि राजनीति रोटी के लिए नहीं राष्ट्र के लिए करनी चाहिए। उनका मानना है कि ''मैं ही सब कुछ नहीं कर सकता बल्कि लोग मिलकर ही सभी काम कर सकते हैं।'' चुनौतियों का डटकर सामना करना उनका मूल स्वभाव है। वे संकट के समय घबराते नहीं बल्कि संकट से दो–दो हाथ करने को तैयार रहते हैं।

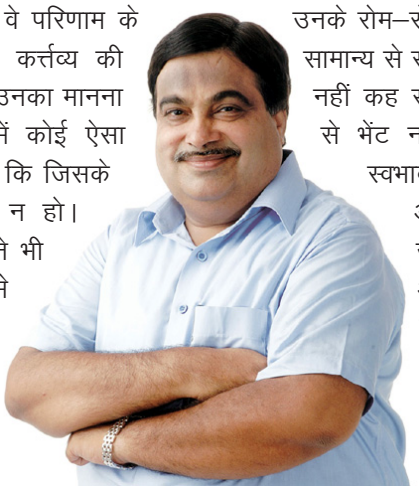

एक दुर्घटना में पैर में चार स्थानों से हड्डी टूटने के बाद भी वे पैर में लगे लोहे के छड़ की चिंता न करते हुए भी अपने प्रवास की अबाध गति को कभी विराम नहीं देते हैं। सहजता, सरलता उनके रोम–रोम में रची–बसी है। सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता यह नहीं कह सकता कि नितिनजी से भेंट नहीं हुई है। उनका स्वभाव समाधानकारी है। अच्छी सलाह की वो उम्र नहीं देखते। अगर छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने भी संगठन हित में कोई सुझाव दिया है तो वे उसे सहज शिरोधार्य कर लेते हैं। बड़ों का सम्मान, बराबर के कार्यकर्ताओं से मित्रता और अपने से छोटे कार्यकर्ताओं को स्नेह में पिरोने की उनमें अद्भुत क्षमता है। ईमानदारी, निष्ठा, प्रामाणिकता, नैतिकता से वे ओत–प्रोत रहते हैं और उनकी अपेक्षा भी यही रहती है कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता में यह गुण होने चाहिए। अटल और आडवाणीजी को वो अपना 'रोल–मॉडल' मानते हैं। वे अत्यधिक आधुनिकता के करीब रहने के बाद भी पुरातन और परंपरा को सदैव साधते हुए चलने की सलाह देते हैं। वे नव–प्रयोगवादी हैं। समय के साथ चलने के आदी भी हैं। वे कृषि आधारित विषयों के जानकार भी हैं साथ ही उनके जीवन का सपना है कि कृषि प्रधान देश का किसान खुशहाल होना चाहिए। उनका मन उस समय बहुत आहत हो जाता है कि वे सुनते हैं कि किसानों ने आत्महत्या कर ली। वे गिरे हुए को उठाने में अधिक विश्वास रखते हैं और उठे हुए को गिराने में उनका कोई विश्वास नहीं रहता है। दांव–पेंच की राजनीति से दूर सामूहिकता–समन्वय

नितिन जी वर्तमान से अधिक और भविष्य से ना के बराबर जुड़े रहते हैं। उनका मानना है कि जीवन में अतीत की चर्चा कम और भविष्य की चिंता भी अनावश्यक ना करते हुए वर्तमान की जीवंतता में सदैव काम करते रहना चाहिए। खास करके राजनीतिक क्षेत्र में इस बात का बहुत असर रहता है कि आप क्या हैं? पर नितिनजी का यह विश्वास है कि अगर आप आदर्श कार्यकर्ता हैं तो आपकी कभी कोई अवहेलना नहीं कर सकता।

के करीब, एकजुटता की मानसिकता, कार्य में निरंतरता, स्वभाव में सौहार्दता, प्रवास में गतिशीलता का संदेश वे हर कार्यक्रम में देने का प्रयत्न करते हैं। 'अन्त्योदय और सर्वोदय' राजनीति से कम, रचनात्मक कार्यों से अधिक होगा यह उनकी दृढ़ धारणा है। यही कारण है कि वे अपने पहले अध्यक्षीय उद्‌बोधन से लेकर अब तक सम्पन्न सभी उद्‌बोधनों में इस बात पर सदैव जोर देते हैं कि जीवन को रचनात्मक राजनीति से जोड़ना चाहिए।

नितिन जी वर्तमान से अधिक और भविष्य से ना के बराबर जुड़े रहते हैं। उनका मानना है कि जीवन में अतीत की चर्चा कम और भविष्य की चिंता भी अनावश्यक ना करते हुए वर्तमान की जीवंतता में सदैव काम करते रहना चाहिए। खास करके राजनीतिक क्षेत्र में इस बात का बहुत असर रहता है कि आप क्या हैं? पर नितिनजी का यह विश्वास है कि अगर आप आदर्श कार्यकर्ता हैं तो आपकी कभी कोई अवहेलना नहीं कर सकता। उनकी बेबाक टिप्पणी कभी–कभी खबरों की सुर्खियां बन जाती हैं। उसका मूल कारण है कि वे 'कैलकुलेटेड' राजनीतिज्ञ नहीं बल्कि 'डेडिकेटेड' राजनीतिज्ञ हैं। उनका बाल स्वभाव ही वरिष्ठ अधिकारियों से सहज ही स्नेह प्राप्त कर लेता हैं। कम समय में राष्ट्रीय परिदृश्य पर उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया है। इस समय उनकी पैनी नजर और सारी योजना देश के सबसे बड़े राज्य में होने वाले विधानसभा निर्वाचन में लगी है। उत्तर प्रदेश के चुनावी यज्ञ में वे सभी भूले–बिसरे गीतों को याद करने का जहां आग्रह कर रहे हैं वहीं सब मिलकर इस यज्ञ में अपनी–अपनी आहुति दें, ऐसा निवेदन भी कर रहे हैं। कम समय में उन्होंने अनेक देशों का दौरा कर अपने दिल की नीति–रीति और सिद्धांतों से वहां के राजनेताओं को अवगत कराने में सफलता प्राप्त की है। उनकी राजनीतिक क्षमता का आंकलन और मूल्यांकन आए दिन राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा अपने–अपने स्तंभों में किया जाता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में उनकी मान्यता बहुत साफ है वे अक्सर कहते हैं कि अनावश्यक प्रचार से बचना चाहिए पर आवश्यक प्रचार से जुड़े भी रहना चाहिए। जन–जन तक अपनी बात पहुंचाने का मीडिया ही सरल माध्यम है।

नितिनजी जबसे अध्यक्ष बने तबसे उन्होंने हर जगह एक ही बात कहना शुरु की कि भाजपा को 10 फीसदी मत हर हाल में बढ़ाना है। उन पर इस बात की धुन सवार है और वे चाहते हैं कि देशभर के कार्यकर्ता भाजपा के मतों में 10 फीसदी का इजाफा करने में प्राण–पण से जुट जाएं।

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से भारत की राजनैतिक राजधानी दिल्ली तक की यात्रा में नितिन जी ने बहुत उतार–चढ़ाव देखे और देख रहे हैं पर उनका मानना है कि यदि मन में मातृभूमि की सेवा का जज्बा हो तो कार्य करने में कहीं पर भी कोई अड़चन नहीं आ सकती।

उनका दो वर्ष का कार्यकाल कार्यकर्ताओं के लिए जहां उत्साह भरा कहा जा सकता है वहीं विविध क्षेत्रों में भाजपा को ले जाने का उनके द्वारा जो सफलतम प्रयोग शुरु किया गया है उनकी सर्वत्र सराहना की जा रही है।■

(लेखक मध्य प्रदेश भाजपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य हैं)

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से भारत की राजनैतिक राजधानी दिल्ली तक की यात्रा में नितिन जी ने बहुत उतार–चढ़ाव देखे और देख रहे हैं पर उनका मानना है कि यदि मन में मातृभूमि की सेवा का जज्बा हो तो कार्य करने में कहीं पर भी कोई अड़चन नहीं आ सकती। उनका दो वर्ष का कार्यकाल कार्यकर्ताओं के लिए जहां उत्साह भरा कहा जा सकता है वहीं विविध क्षेत्रों में भाजपा को ले जाने का उनके द्वारा जो सफलतम प्रयोग शुरु किया गया है उनकी सर्वत्र सराहना की जा रही है।

वर्तमान संदर्भ में पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता

लेख आमंत्रण

'कमल संदेश' में प्रकाशनार्थ ''वर्तमान संदर्भ में पं. दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता'' पर ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी लेख आमंत्रित किए जाते हैं। एकात्म मानववाद के प्रणेता एवं हमारे प्रेरणास्रोत पं. दीनदयाल उपाध्याय ने अपना सम्पूर्ण जीवन मां भारती के गौरव और महिमा को बढ़ाने में लगा दिया। हमारा उनके सहयोगियों, सहकर्मियों, शोधकर्ताओं, लेखकों और पत्रकारों से अनुरोध है कि वे 'कमल संदेश' में अपने लेख भेजकर उनकी 'विचार यात्रा' के प्रकाशन में अपना सहयोग दें।

çHkkr >k] lkln
lEikn

लोकलुभावन नीतियों के खतरे

cychj iqt

V र्थशास्त्री होने के कारण 'खाद्य सुरक्षा विधेयक' की खामियां और उसके कारण राजकोष और देश को होने वाले खामियाजे की पूरी समझ होने के बावजूद प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को अंततः कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के दबाव में झुकना पड़ा। सरकार द्वारा पारित खाद्य सुरक्षा विधेयक के अनुसार देश की 63 प्रतिशत आबादी को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। 3 रूपए किलो चावल, 2 रूपए किलो गेहूं और एक रूपए किलो की दर से मोटा अनाज उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राजस्व पर 27,663 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा और खाद्य सब्सिडी 95,000 करोड़ रूपए हो जाएगी। कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रूपए के निवेश की जरूरत होगी। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि वास्तविक खाद्य सब्सिडी एक लाख 30 हजार करोड़ रूपए से अधिक हो जाएगी। गेहूं और चावल के समर्थन मूल्य में वृद्धि के साथ–साथ यह राशि और बढ़ती जाएगी।

सवाल संसद में कानून बना देने का नहीं है। प्रश्न उसके तार्किक परिणामों का है। सरकार 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी की खाद्य सुरक्षा देने का दावा कर रही है, जिनमें क्रमशः 46 प्रतिशत और 28 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे वाले सरकारी प्राथमिकता में होंगे। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में यह निर्णय तो कर लिया, किन्तु गरीबी रेखा का मापदंड क्या है? इस संबंध में तेन्दुलकर समिति, अर्जुन सेनगुप्ता समिति, योजना आयोग और अन्य संबद्ध इकाइयों के आंकड़ों में भारी विरोधाभास है। सरकार यह वरीयता सूची कैसे निर्धारित करेगी? क्या मौजूदा वितरण प्रणाली को दुरूस्त किए बिना गरीबों व वंचितों तक खाद्यान्न की आपूर्ति संभव है?

पिछले वित्त वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में राशन प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। इसके अनुसार राशन प्रणाली में आधे से ज्यादा खाद्यान्न चोरी हो जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सस्ती दर वाला 60 प्रतिशत गेहूं और 20 प्रतिशत चावल गरीबों तक पहुंचने से पहले ही हज्म हो जाता है। सरकार ने संसद में यह भी स्वीकार किया है कि पूर्वोत्तर राज्यों के राशन का पूरा अनाज खुले बाजार में बिकने के लिए पहुंच जाता है। खाद्यान्न की यह लूट भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से लेकर राशन दुकानों तक होती है। राशन प्रणाली में इस समय 35 करोड़ लोगों को सस्ता खाद्यान्न वितरित किया जाता है। प्रस्तावित विधेयक में 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा में लाने का दावा किया गया है। पहले से ही खस्ताहाल राशन प्रणाली पर विश्वास का क्या कारण है? क्यों खाद्यान्न के लुटेरों पर नकेल कसने की बजाय सरकार उन्हें और लूट मचाने का मौका दे रही है? विधेयक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों की 75 प्रतिशत आबादी में से 46 और 50 शहरी आबादी में से 29 गरीबों को अनाज राशन प्रणाली के द्वारा दिया जाना तय किया गया है। राशन प्रणाली में सुधार के लिए सरकार ने इसके कम्प्यूटरीकरण, राशन कार्ड को 'आधार' से जोड़ने और कूपन व्यवस्था शुरू करने की बात की थी। इस दिशा में अब तक जहां कोई प्रगति नहीं है, वहीं सरकार की महत्वाकांक्षी 'आधार' योजना ही अब स्वयं 'निराधार' हो गई है।

सवाल संसद में कानून बना देने का नहीं है। प्रश्न उसके तार्किक परिणामों का है। सरकार 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी आबादी की खाद्य सुरक्षा देने का दावा कर रही है, जिनमें क्रमशः 46 प्रतिशत और 28 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे वाले सरकारी प्राथमिकता में होंगे। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए जल्दबाजी में यह निर्णय तो कर लिया, किन्तु गरीबी रेखा का मापदंड क्या है? इस संबंध में तेन्दुलकर समिति, अर्जुन सेनगुप्ता समिति, योजना आयोग और अन्य संबद्ध इकाइयों के आंकड़ों में भारी विरोधाभास है। सरकार यह वरीयता सूची कैसे निर्धारित करेगी? क्या मौजूदा वितरण प्रणाली को दुरूस्त किए बिना गरीबों व वंचितों तक खाद्यान्न की आपूर्ति संभव है?

इस योजना को लागू करने के लिए 610 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सरकार कहां करेगी? देश में अभी 415 लाख टन खाद्यान्न रखने की व्यवस्था है, वहीं करीब 190 लाख टन अनाज महज पन्नियों आदि से ढक कर रखे जाते हैं। उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल लाखों टन अनाज, फल और सब्जियां सड़ जाती हैं। हर साल 58 हजार करोड़ रुपए के अनाज के बर्बाद होने की बात स्वयं सरकार ने स्वीकार की है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए पिछले साल जुलाई माह में सरकार को गरीबों के बीच अनाजों के मुफ्त विरतण का निर्देश दिया था, किन्तु आज खाद्य सुरक्षा कानून बनाने वाली सरकार ने तब हाथ खड़े कर दिए थे। क्यों?

इस विधेयक का प्रारूप सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने तैयार किया है, इसलिए खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री की प्रारंभिक आपत्तियों के बावजूद इसका पारित होना आश्चर्यजनक नहीं है। किंतु क्या ऐसी अवसरवादी नीतियों से वांक्षित लक्ष्य प्राप्त कर पाना संभव है? पिछले साल सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाया था। सर्व शिक्षा अभियान पर भी सरकार को गर्व है। किंतु सरकारी शिक्षण संस्थानों की बदहाली पर कोई ध्यान नहीं है। समाज के कमजोर तबके का व्यक्ति भी अपने बच्चों को निजी शिक्षण संस्थानों में शिक्षा दिलाने की इच्छा क्यों रखता है? सरकारी विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का अभाव जैसे उसकी पहचान बन गई हो। देश में अभी 5.23 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहीं सरकार के उपरोक्त अधिनियम के बाद 5.1 लाख अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता है। कई राज्यों में सरकारी विद्यालय पेड़ों की छांव में चलते हैं तो कहीं शिक्षकों के वेतन महीनों से लंबित हैं। इसकी तुलना में निजी शिक्षा संस्थानों का प्रदर्शन बेहतर होना स्वाभाविक है।

यह केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र के संस्थानों, उपक्रमों की यही कहानी है। अस्पतालों को ही लें। सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की कमी के कारण बेहतर चिकित्सा लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, आए दिन मरीजों को डाक्टरों की हड़ताल का खामियाजा भोगना पड़ता है।

मरीजों के लिए जहां पर्याप्त संख्या में बैड नहीं होते, वहीं मरीजों के तमारदारों को अस्पताल के बाहर खुले में रात गुजारनी पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रति हजार आबादी पर अस्पतालों में 3 बैड होना निर्धारित है और उसकी तुलना में भार में यह अनुपात मात्र 0.9 है। स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध कार्य गौण है। आधारभूत संरचनाओं में तेजी से विकास करना भारत की सबसे बड़ी जरूरत है, परन्तु अवसरवादी राजनीति करने वालों को इसकी चिंता नहीं होती।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को बेहतर करने एवं लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का प्राथमिक दायित्व है, किन्तु मूलभूत सुधार और समुचित व्यवस्था का निर्माण किए बगैर जिस तरह खाद्य सुरक्षा कानून बनाया गया, वह राजकोष की बर्बादी मात्र है। लोकलुभावन नीतियों को अर्थव्यवस्था पर तो प्रतिकूल असर पड़ता ही है, लक्षित समूह भी वांछित लाभ से वंचित रह जाता है। समृद्ध–सुरक्षित व भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त भारत का निर्माण तभी संभव है, जब भारत की अंतिम सीढ़ी पर बैठे व्यक्ति तक विकास का फल पहुंचे। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था और चुनाव जीता था। कैसी विडम्बना है कि आज चालीस साल बाद उनका ही पौत्र राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में गरीबी मिटाने का संकल्प दोहराता है। आज सोनिया गांधी इस कानून के माध्यम से देश से भूख मिटाने की प्रतिबद्धता व्यक्त कर रही हैं। क्या इतिहास अपने को दुहरा रहा है? ■

(लेखक भाजपा के राज्यसभा सदस्य हैं)

इस योजना को लागू करने के लिए 610 करोड़ टन अनाज की आवश्यकता होगी। इतनी बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सरकार कहां करेगी? देश में अभी 415 लाख टन खाद्यान्न रखने की व्यवस्था है, वहीं करीब 190 लाख टन अनाज महज पन्नियों आदि से ढक कर रखे जाते हैं। उचित भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल लाखों टन अनाज, फल और सब्जियां सड़ जाती हैं। हर साल 58 हजार करोड़ रूपए के अनाज के बर्बाद होने की बात स्वयं सरकार ने स्वीकार की है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेते हुए पिछले साल जुलाई माह में सरकार को गरीबों के बीच अनाजों के मुफ्त विरतण का निर्देश दिया था, किन्तु आज खाद्य सुरक्षा कानून बनाने वाली सरकार ने तब हाथ खड़े कर दिए थे। क्यों?

असंवैधानिक है अल्पसंख्यक आरक्षण : रविशंकर प्रसाद

लोकपाल विधेयक व पिछड़ा वर्ग आरक्षण में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के सरकार के फैसले से राजनीति गरमाई हुई है। सवाल राजनीतिक भी उठ रहे हैं और संवैधानिक भी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भाजपा के महासचिव व मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का दो टूक कहना है कि धार्मिक आधार पर आरक्षण पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश के चुनावों से पहले वोट बैंक की खतरनाक राजनीति करार देते हुए अल्पसंख्यकों को भी आगाह किया है। nfud tkxj.k *के* jkeukjk;.k JhokLro *ने प्रसाद से इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की। प्रस्तुत हैं चर्चा के प्रमुख अंश–*

- भाजपा ने पिछड़ी जातियों के लिए मंडल आयोग का समर्थन किया था, अब अल्पसंख्यक आरक्षण का विरोध क्यों?

भारत के संविधान में धारा 15 व धारा 16 में मौलिक अधिकारों में साफ लिखा हुआ है कि जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके विकास की कोशिश की जाए। उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, इसका पूरा समर्थन करते हैं। अगर अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए। भारत का संविधान उपासना पद्धति व धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। सरकार का अभी का जो निर्णय है उसमें अल्पसंख्यक आधार पर ही आरक्षण का एक सब कोटा बनाया गया है। धर्म व उपासना पद्धति के आधार पर इस तरह कोटा बनाना असंवैधानिक है। इससे गैर अल्पसंख्यक पिछड़े व अति पिछड़ों का हिस्सा कमजोर होगा।

- आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समुदाय काफी पिछड़ा हुआ है और उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए?

अगर ऐसा कुछ करना है तो विधि सम्मत व संवैधानिक तरीके से ही किया जाए। एक बड़ा सवाल यह भी है कि साठ साल से मुसलमानों के वोट की राजनीति करने वालों ने उन्हें क्या दिया है? उनके लिए शिक्षा, रोजगार, स्वावलंबन जरूरी है। लेकिन यह सब वोट के लिए चुनाव के पहले ही क्यों याद आता है? इस तरह की राजनीति से अल्पसंख्यकों का भला नहीं होगा। वह इस देश के हिस्से हैं। उनका सम्मान है, उनके लिए सद्भाव है, उनके विकास के लिए सहयोग करेंगे, लेकिन उन्हें भी समझना चाहिए कि वोट के लिए अपना उपयोग नहीं होने देंगे।

- जातीय आधार पर आरक्षण को सही मानते हैं तो धार्मिक आधार पर यह गलत क्यों है?

इसलिए, क्योंकि भारतीय संविधान में साफ लिखा हुआ है कि धर्म व जाति के आधार पर विभाजन नहीं किया जाएगा। अगर कुछ जातियां पूरी की पूरी पिछड़ी हैं, अति पिछड़ी हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह एक सच्चाई है कि अनुसूचित जातियां व जनजातियां बहुत पिछड़ी हैं, लेकिन यहां तो अल्पसंख्यक आधार पर पिछड़ों के बीच में एक वर्गीकरण किया गया है, जो अनुचित है।

- आपने अनुसूचित जाति के आरक्षण की बात कही, उसमें भी दलित-इसाई आरक्षण के बारे में बहस छिड़ी हुई है?

भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा, जो हिंदू हैं। इसकी संवैधानिक व्याख्या में सिख, बौद्ध व जैन भी आते हैं। यह इसलिए, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने देखा कि हजारों साल से हिंदू समाज में दलित भेदभाव के शिकार रहे। ऐसा भेदभाव इसाई व मुस्लिम समुदाय में नहीं है। इसलिए दलित इसाई व दलित मुस्लिम की बात कहना संवैधानिक नहीं है। साथ ही साठ साल से इस बारे में देश में संवैधानिक सर्वानुमति रही है, सरकार चाहे किसी की भी क्यों न रही हो।

- लोकपाल विधेयक में भी अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया है। भाजपा उसका विरोध कर रही है। क्या यह विरोध राजनीतिक है?

सरकार जानबूझकर राजनीतिक दबाब में ऐसा विधेयक लेकर आती है जो कोर्ट में अटक जाए। संविधान में आरक्षण के बारे में स्पष्ट व्यवस्था है। यह सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिलता है। संवैधानिक संस्थाओं में आरक्षण नहीं है। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैग, सीवीसी, चुनाव आयोग, लोकसेवा आयोग में आरक्षण नहीं है, क्योंकि यह नौकरी वाली संस्थाएं नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाएं हैं। जब लोकपाल को संवैधानिक संस्था बना रहे हैं वहां आरक्षण पूरी तरह असंवैधानिक है। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? अगर कल कोई आतंकवादी कहे कि न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, इसलिए उसे न्याय नहीं मिलेगा? कोई यह कहे कि मैं इसलिए केंद्रीय सेवा में नहीं आ सकता, क्योंकि लोकसेवा आयोग में आरक्षण नहीं है? चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ सकते हैं। चुनाव आयोग में लिंगदोह व कुरैशी क्या किसी आरक्षण के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त बने?

भारत का संविधान उपासना पद्धति व धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। सरकार का अभी का जो निर्णय है उसमें अल्पसंख्यक आधार पर ही आरक्षण का एक सब कोटा बनाया गया है। धर्म व उपासना पद्धति के आधार पर इस तरह कोटा बनाना असंवैधानिक है। इससे गैर अल्पसंख्यक पिछड़े व अति पिछड़ों का हिस्सा कमजोर होगा।

- पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दों के क्या राजनीतिक परिणाम होंगे?

देखिए, आपकी जब साख गड़बड़ा जाती है तो उस पर कोई भी कलेवर लगाइए साख नहीं बनती है। आज का भारत 2011 का भारत है। जनता सब समझती है और जानती है। वोटों के लिए जानबूझकर यह विभाजन किया गया है। महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, कुशासन, चाहे वह संप्रग का हो, मायावती का हो या मुलायम सिंह का, इससे पीड़ित जनता इस क्षणिक दो महीने की वोट बैंक की राजनीति के झांसे में आ जाएगी, ऐसा मैं नहीं मानता।

- इसका मतलब क्या यह माना जाए कि भाजपा गैर अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग के हितों को चुनावी मुद्दा बनाएगी?

हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो अल्पसंख्यक पिछड़े होने की वजह से आरक्षण के दायरे में आते हैं उनका हम समर्थन करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों का वर्गीकरण कर व्यापक हिंदू समाज के पिछड़ों व अति पिछड़ों के हक को मारा जाएगा तो हम इसका विरोध करेंगे।

- आपके सहयोगी जनता दल (यू) ने तो इससे भी आगे बढ़कर रंगनाथ मिश्र आयोग की अल्पसंख्यकों को १५ फीसदी आरक्षण दिए जाने की मांग की है?

रंगनाथ मिश्र आयोग दलित ईसाई व दलित मुसलमानों के मुद्दे पर बना था। उस पर हमारे व उनके बीच तमाम मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सामाजिक न्याय आंदोलन से उपजी राजनीति की सभी ताकतों को इस तरह के असंवैधानिक आरक्षण का विरोध करना चाहिए।

- संविधान में तो ५० फीसदी आरक्षण की ही अनुमति है, लेकिन कई राज्यों में तो इससे ज्यादा है?

वह मामला अभी सुप्रीमकोर्ट में संविधान पीठ के सामने लंबित है। कभी भी धर्म आधारित आरक्षण को अनुमति नहीं दी गई। जनता एक मजबूत लोकपाल की जरूरत महसूस करती है, जिसका भाजपा पूरा समर्थन करती है। अब यह सरकार इस पूरे फोकस को बदलने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। ■

मुख्य चुनाव आयुक्त को भाजपा ने सौंपा ज्ञापन

सेवा में

दिनांक 13.12.2011

मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त महोदय,
निर्वाचन सदन, नई दिल्ली– 110001

महोदय,

आने वाले दिनों में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रहा है, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में चुनावों से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश में चौतरफा भय, अराजकता एवं निष्पक्ष, भयमुक्त, चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। यह काम बसपा सरकार के संरक्षण में तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते भयमुक्त, स्वतंत्र चुनाव एक बड़ी चुनौती होगी। बसपा सरकार में उच्च पदों पर बैठे कुछ अधिकारी बसपा कार्यकर्ता और प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं, यहां तक कि कई जिलों में पोलिंग बूथों के मनमाने परिवर्तन, मतदाता सूचियों में फेरबदल और बीएलओ की नियुक्तियों में भी सीधे हस्तक्षेप एवं निर्देश दे रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को चिह्नित कर तत्काल उच्च सरकारी पदों से हटाना एवं कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। ऐसे ही कुछ अधिकारी जो कि बसपा प्रवक्ता– नेता की भूमिका निभाते रहे हैं कि प्रमाण हेतु सीडी संलग्न है।

ऐसे ही अधिकारियों के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतदाता सूचियों से क्षेत्रों एवं सम्प्रदायों को चिह्नित कर नाम जोड़े एवं काटे गये, मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा क्षेत्र में बड़े पैमानें पर मतदाता सूचियों में 5 से 10 वर्षों तक के नाबालिग बच्चों का नाम अंकित होना एवं कई क्षेत्रों मे बड़े पैमाने पर मतदाताओं का फर्जी नाम जोड़ने–काटने के प्रमाण स्वरूप मतदाता सूची एवं सरकारी परिवार रजिस्टर साथ में संलग्न कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है जिससे की जिन विधानसभा क्षेत्रों में 2009 की मतदाता सूची के बाद आश्चर्यजनक तरीके से बड़ी संख्या में मतदाताओं की बढ़ोतरी या नाम काटे गये हैं उनका पुनः निरीक्षण कर इसे ठीक किया जाये एवं दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाये।

चुनावों के प्रचार के दौरान जहाज एवं हैलिकाप्टर से प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों को 'सरकारी कर्मचारियों द्वारा सही को–आर्डिनेट ना उपलब्ध कराने की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है' उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा सभी हवाई पट्टियों को जिलाधिकारी के अधीन करने के चलते अनुमति की प्रक्रिया और भी जटिल हो गयी है। जिलाधिकारी बहाने बनाकर विपक्षी पार्टियों को अनुमति नहीं देते हैं। इस व्यवस्था के चलते चुनावों में बड़े पैमाने पर भेदभाव से कठिनाई होगी। पहले की तरह हवाई पट्टियों की अनुमति की व्यवस्था नगर विमानन विभाग के पास रहना ही ठीक होगा एवं निर्देश दिया जाये कि प्रशासन राजनैतिक दलों को समय से एवं सही को–आर्डिनेट उपलब्ध कराये।

बड़े पैमाने पर डमी उम्मीदवारों की लम्बी फौज मतदान एवं चुनावी प्रक्रिया में समस्या का कारण बनती है, देखा गया है कि अधिकांश डमी उम्मीदवार कुछ राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा पोलिंग एजेंट, काउंटिंग एजेंट, इलैक्शन एजेंट आदि की लालच में खड़े किए जाते हैं यदि राजनैतिक पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए पोलिंग, काउंटिंग एवं इलैक्शन एजेंटों की संख्या दो गुनी कर दी जाये तो इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो सकता है।

उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र जैसे मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर आदि क्षेत्रों में मतदान की तिथि छुट्टियों के दिन रखी जाये क्योंकि वहां रहने वाले मतदाता बड़ी संख्या में दिल्ली में नौकरी या व्यापार करते हैं और वर्किंग दिवस होने के कारण वे मतदान से वंचित हो जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में हर माह बड़े पैमाने पर उच्च पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की जाति एवं बसपा के साथ नजदीकी के आधार पर ट्रांस्फर–पोस्टिंग हो रही है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चुनाव आयोग को चुनाव की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर ऐसे अधिकारियों पर नजर रखनी चाहिए और चुनावी व्यवस्था से उन्हें अलग करना चाहिए। लगभग 32 जिलों ऐसे अधिकारियों की सूची उपयुक्त समय पर चुनाव आयोग की जानकारी हेतु पार्टी प्रेषित की जायेगी।

कलराज मिश्रा	मुख्तार अब्बास नकवी	सूर्यप्रताप शाही	डॉ. रमापतिराम त्रिपाठी
आर. रामकृष्ण	बाबा पाटिल	श्रीकांत शर्मा	राजन खोसला ■

सुशासन दिवस पर हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश से भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प किया

भारत को सुखी, संपन्न और भ्रष्टाचार मुक्त देश बनायेंगे - नितिन गडकरी

I oknnkrk }kjk

Hkk रतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 87वें जन्मदिवस पर 25 दिसम्बर 2011 को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब लॉन में आयोजित विशाल जनसभा में 10 हजार से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी और प्रदेश अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में संकल्प किया कि वे देश से कांग्रेस सरकार का कुशासन समाप्त करके भारतीय राजनीति का भविष्य बदलेंगे। राज ही नहीं समाज भी बदलेंगे। श्री नितिन गडकरी ने उपस्थित जनसमूह के बीच घोषणा की कि भाजपा भारत को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली देश बनाएगी। जनसभा की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने की।

जनसभा को श्री नितिन गडकरी के अलावा वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, अनंत कुमार, प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा, वाणी त्रिपाठी और रामेश्वर चौरसिया ने भी संबोधित किया। मंच पर श्री रामलाल, नवजोत सिंह सिद्धू, रजनी अब्बी, डॉ. हर्षवर्धन, मांगेराम गर्ग, ओ.पी. कोहली, जगदीश मुखी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, सुभाष आर्य आदि नेतागण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन आशीष सूद ने किया। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे – अटल बिहारी वाजपेयी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तख्त बदलेंगे, ताज बदलेंगे, बेईमानों का राज बदलेंगे।

श्री गडकरी ने कहा कि भीषण कुशासन के मनमोहन युग में लोग वाजपेयी सरकार के 6 वर्षीय सुशासन को याद करते हैं। अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में खाद्य पदार्थों तथा दैनिक आवश्यकता की हर वस्तु के दाम स्थिर थे। विदेशी मुद्राकोष शीर्ष पर था। मुद्रास्फीति का नामोनिशान नहीं था। वाजपेयी सरकार ने कच्छ को कोहिमा और कन्याकुमारी को कश्मीर से चौड़ी सड़कों से जोड़ा था। डॉलर के मुकाबले रूपया, 36 के मूल्य पर स्थिर था। रूपये का अवमूल्यन 1 डॉलर के मुकाबले 56 रूपये तक हो गया है। वाजपेयी शासन में सकल घरेलू विकास दर 8 प्रतिशत के आंकड़े को पार कर गई थी। उड़ीसा के भयानक चक्रवात, गुजरात के भूकंप और कारगिल युद्ध

होने पर भी देश में मंहगाई और भ्रष्टाचार का नामोनिशान नहीं था। उन्होंने कहा कि भाजपा पुनः देश को राजग शासन जैसा स्वर्ण युग लौटाएगी।

श्री वेंकैया नायडू ने कहा कि श्री वाजपेयी टॉलेस्ट पॉलीटिकल लीडर, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन, बेस्ट पीएम तथा बेस्ट ओरेटर हैं। उनके जैसा कोई अन्य राजनीति पुरूष भारतीय राजनीति में पैदा नहीं हुआ। वाजपेयी शासन के दौरान देश में विकासात्मक अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुये। उन्होंने समस्त देश की कनेक्टिविटी को रेल, रोड, बंदरगाह, दूरसंचार, दृश्य श्रव्य माध्यमों से जोड़ा था। राजग शासन ने भारत का चेहरा ही बदलकर रख दिया था। पहली बार देश के 50 हजार लोगों को टेलीफोन कनेक्शन दिये गये। 500 नये टी.वी. चैनल खुले। देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली चौड़ी सड़कें मिलीं। नदियों को जोड़ने की दूरगामी योजना वाजपेयी सरकार ने ही बनाई थी। आज संप्रग सरकार में जनता मंहगाई, भ्रष्टाचार, घोटालों, आतंकवाद के आतंक से रो रही है और देश का प्रधानमंत्री सो रहा है।

पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वाजपेयी जी धरती के सपूत थे। वे भारत की जमीनी सच्चाई को अच्छी तरह समझाते थे। इसी कारण राजग शासन में जिसने भी नीतिगत निर्णय हुये वे आम आदमी, गांव, गरीब, किसान, मजदूर और बेसहारा लोगों को ध्यान में रखकर किये गये। उन्होंने पोखरन परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु बम बनाने वाले देशों की श्रेणी में एक सशक्त तथा गौरवयुक्त राष्ट्र के रूप में सम्मिलित किया। उनकी लाहौर बस यात्रा इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत शत्रुता में नहीं मित्रता में विश्वास करता है। प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने वाजपेयी जी के जीवन से जुड़े अनेक संस्मरण सुनाये। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने 50 साल के शासन में देश को तबाह किया है। 1947 के कश्मीर पर पाक आक्रमण का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि यदि भारतीय सेनाओं को 2–3 दिन का मौका नेहरू सरकार दे देती तो आज सारा कश्मीर और रावलपिंडी तक भारत का शासन होता।

प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक की 61 वर्षीय राजनीति में उनके जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी जी से राजनीति का और समन्वय का ककहरा पढ़ा था। वाजपेयी जी सभी के लिये मार्गदर्शक, प्रेरणास्रोत बने हुये हैं। भारतीय राजनीति में 6 दशक तक उन्होंने यह संकल्प लेकर राजनीति की कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर सुख, संतोष और संपन्नता की मुस्कान बिखेरनी है। अपने संस्मरण सुनाते हुये श्री गुप्ता ने कहा कि वाजपेयी जी ने उन्हें मूलमंत्र दिया था कि आम आदमी, गरीब आदमी, मजबूर आदमी को ध्यान में रखकर ही विकास की समस्त योजनाएं बनाओ, ऐसे फैसले किये जाएं जिसमें समाज और सर्वजन का हित हो। ■

राज्य सभा

किसान-आत्महत्या मुद्दे पर गंभीरता से सोचे सरकार : रुद्रनारायण पाणि

गत 15 दिसम्बर 2011 को राज्यसभा में ''देश में वर्तमान कृषि संकट के परिणामस्वरूप किसानों द्वारा आत्महत्याएं किए जाने से उत्पन्न स्थिति'' पर हुयी चर्चा के दौरान भाजपा सांसद श्री रुद्रनारायण पाणि द्वारा दिए गए भाषण का सारांशः

आज देश के कई प्रांतों जैसे पंजाब, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और बंगाल आदि में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हर दिन 47 किसान आत्महत्या करते हैं और आधे घंटे में एक आत्महत्या होती है। उड़ीसा में सन 2009 से 2011 तक तीन सालों में लगभग 252 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना बंद हों। 2004 से केन्द्र में जो यूपीए की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मैं उसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूं। देश में भूमि सुधार परिषद का प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित हुए साढ़े तीन साल हो गए हैं, लेकिन इसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। उड़ीसा में किसानों की जो आत्महत्या की जो आत्महत्या हो रही है, उस पर गंभीरता से सोचें। मैं माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब वे उत्तर देंगे, तो कम से कम उसके बारे में अवश्य सूचना देंगे। जब कपास का किसान माल लेकर सी.सी.आई. के सामने आता है, तब सी.सी.आई. उसको उचित कीमतें नहीं देती है, वह बिचौलिया ही ले लेते हैं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि सी.सी.आई. में हो रही धांधली के प्रति उनको ध्यान देना होगा। ■

शीला के 3 वर्षीय कुशासन पर भाजपा ने जारी किया श्वेत-पत्र

fnल्ली की भ्रष्ट, जनविरोधी और तानाशाह सरकार के तीन विफल और नकारा वर्ष पूर्ण होने पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता ने 17 दिसम्बर को दिल्ली सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा 400 प्रमुख स्थानों पर चलाए जा रहे दो दिवसीय हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लेते हुए आजादपुर चौक पर सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया। उन्होंने मॉडल टाउन, कल्याण विहार, आजादपुर चौक आदि के हस्ताक्षर अभियानों में हिस्सा लिया। इस अभियान में पार्टी के 30,000 से अधिक कार्यकर्ताओं ने लाखों नागरिकों के हस्ताक्षर सरकार विरोधी प्रपत्र पर कराए। जनता के हस्ताक्षरयुक्त प्रपत्र राष्ट्रपति महोदया को सौंपकर उनसे दिल्ली सरकार के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने की मांग पार्टी करेगी।

दिल्ली को पेरिस तथा शंघाई बनाने का वायदा करने वाली दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने सरकार बनने के बाद वायदा किया था कि दिल्ली को स्लममुक्त, कचरामुक्त राजधानी बनाएगी। दिल्ली को स्लममुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने यहां के लाखों गरीबों से वायदा किया था कि उनके लिए राजीव रत्न योजना में सस्ते और मजबूत मकान बनाकर उनके वर्तमान झुग्गी स्थल पर ही बहुमंजिली इमारतें बनाकर दिए जायेंगे। एक भी मकान किसी भी स्लम या झुग्गीवासी को नहीं दिए गए हैं।

2008 के विधानसभा चुनावों के पहले अक्तूबर 2008 में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली की हजारों अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के हाथों से प्रॉविजनल सर्टिफिकेट जारी करवाए थे। लोगों से वायदा किया गया था कि कालोनियों को नियमित करने के उनमें सभी मूलभूत सुविधाएं एक साल के अंदर उपलब्ध करा दी जायेंगी। आज तक एक भी कालोनी को नियमित नहीं किया गया है। प्रॉविजनल सर्टिफिकेट बांटने के नाम पर भी अरबों रूपए का भूमि घोटाला सरकार और राजधानी के भू–माफिया ने मिलकर किया है। ऐसी अनेक फर्जी अनधिकृत कालोनियों को प्रॉविजनल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं जहां कोई आबादी ही नहीं है। अब यह घोटाला सामने आ जाने के बाद सरकार मामले को दबाने में जुटी हुई है। दिल्ली में कमरतोड़ भीषण मंहगाई के कारण 80 प्रतिशत दिल्लीवासियों को भरपेट पौष्टिक भोजन नसीब नहीं है। मंहगाई घटाना तो दूर मुख्यमंत्री ने जले पर नमक छिड़कते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता ज्यादा पैसा कमाती है इसलिए उस पर मंहगाई का कोई असर नहीं है। दिल्ली में मंहगाई देश भर के शहरों के मुकाबले सबसे अधिक है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स न घटाकर मंहगाई को बढ़ाने का ही काम किया है। सर्किल रेट, वैट, सर्विस टैक्स, रजिस्ट्री फीस वृद्धि, स्कूलों की फीस वृद्धि, बिजली, पानी तथा सीवरेज चार्ज में वृद्धि आदि फैसलों से जनता का दिल्ली में रह पाना मुश्किल हो गया है।

अक्तूबर 2010 में सम्पन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कुल 70,000 करोड़ रूपए का घपला सरकार ने किया था। इस घोटाले में 25,000 करोड़ रूपए का भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार ने किया था। इसकी पुष्टि शुंगलू कमेटी तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने की है। दोनों संवैधानिक संस्थाओं ने घपलों की सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है लेकिन दिल्ली सरकार ने इन रपटों को नकार दिया है। शुंगलू कमेटी का गठन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था। रिपोर्ट आए 6 महीने से अधिक का समय बीत गया है लेकिन केन्द्र सरकार इस पर कोई कार्यवाही करने से अब तक बच रही है। इस प्रकार केन्द्र सरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्टाचार करने के बाद भी बचाने का खुला प्रयास कर रही है। दिल्ली में सरकार ने बिजली का निजीकरण करके हजारों करोड़ रूपए का घोटाला किया था। बिजली निजीकरण के फायदे भी जनता को नहीं मिले। बिजली के मूल्य बराबर बढ़ाए गए। लोगों के घरों में तेज विद्युत खपत रिकार्ड करने वाले घटिया विद्युत मीटर लगाकर उनका बिजली बिल तीन गुना तक बढ़ा दिया गया है। अब सरकार पानी का भी निजीकरण करने की योजना तैयार कर चुकी है। धीरे–धीरे इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। पानी का निजीकरण होने के बाद दिल्ली में पानी पीना भी दुश्वार हो जाएगा। दिल्ली की 40 प्रतिशत जनता को सरकार पीने का पानी तथा 20 प्रतिशत जनता को बिजली नहीं उपलब्ध करा पाई है। इन लोगों को बिजली और पानी के लिए निजी साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवक–युवतियों को हर साल भटकना पड़ता है। सरकार ने 13 वर्ष के शासनकाल में एक भी विश्वविद्यालय नहीं खोला है। ■

आंध्र प्रदेश में बुनकरों की समस्याएं उजागर करने के लिए भाजपा का त्रि-दिवसीय अनशन

'भाजपा का लक्ष्य गरीबों के जीवन को बेहतर बनाना है'

&l;oknnkrk }kjk

Hkk जपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि वह बुनकरों को गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में शामिल करेंगे और यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो उनके ऋणों को माफ कर दिया जाएगा। भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री पी. मुरलीधर राव द्वारा हैदराबाद में बुनकरों की समस्याओं को उजागर करने के लिए त्रि–दिवसीय अनशन की समाप्ति के अवसर पर एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने बुनकरों को निःशुल्क बिजली प्रदान करने का वायदा भी किया।

केन्द्र में कांग्रेसनीत सरकार द्वारा बुनकरों की उपेक्षा किए जाने पर उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार को चेताने के लिए एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और श्री गडकरी पार्टी के सांसदों के शिष्टमण्डल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपनी बात पहुंचाने के लिए अगुवानी भी करेंगे।

उन्होंने कहा कि श्री राव के अनशन ने सरकार का ध्यान इस दिशा में खींचा है और देश के बुनकरों की दयनीय दशा से अवगत कराया है। यह बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में 2000 से भी अधिक बुनकरों ने आत्महत्याएं की हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई आसमान छू रही है, और कामगार, मछुआरे और बुनकरों सहित निर्बल वर्ग के लोगों के लिए एक जून का खाना भी जुटाना मुश्किल हो रहा है। श्री गडकरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नीत सरकार की गलत नीतियों और भ्रष्ट प्रशासन ने देश को तबाह करके रख दिया है।

श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा का लक्ष्य गरीबों का जीवन बदल कर बेहतर बनाना है और हमें विश्वास है कि भाजपा–नीत एनडीए केन्द्र और अधिकांश राज्यों में सत्ता में लौटेगी। जब तक बुनकरों की मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, यह संघर्ष जारी रहेगा और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे गरीबों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सड़कों पर आ कर संघर्ष करें।

आंध्र प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जी. किशन रेड्डी ने मांग की कि सरकार बुनकरों की जनसंख्या के अनुपात में उनके लिए बजट का आबंटन करे ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें तथा उनकी दशा सुधारने के लिए की गई राशि के बारे में श्वेत पत्र जारी किया जाए। भाजपा उपाध्यक्ष और आंध्र प्रदेश प्रभारी श्री पुरूषोत्तम रूपाला, भाजपा तमिलनाडु प्रदेशाध्यक्ष श्री राधाकृष्णन, भाजपा राष्ट्रीय सचिव श्री पी. मुरलीधर राव, अखिल भारतीय भाजपा बुनकर प्रकोष्ठ संयोजक श्री बसंत कुमार ने भी इस अवसर पर अपने विचार प्रगट किए।■

भाजपा मणिपुर में विकास के मुद्दों पर प्रमुख ध्यान देगी : नितिन गडकरी

इम्फाल में 20 दिसम्बर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारी पार्टी सम–विचारधारा रखने वाली पार्टियों के साथ मिलकर अगले वर्ष फरवरी में होने वाले संभावित दसवें विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का मुकाबला करेगी, जिसमें एनसीपी और क्षेत्रीय मणिपुर पीपुल पार्टी ने चुनाव–पूर्व गठबंधन की घोषणा कर दी।

श्री नितिन गडकरी ने इम्फाल की अपनी दो दिन का चुनावी दौरा समाप्त करते हुए मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमने चुनावों से पूर्व मणिपुर में एक साझा विपक्ष बनाने के लिए कुछ पार्टियों से विचार–विमर्श किया है।

यद्यपि भाजपा को आगामी चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र तैयार नहीं किया है, परन्तु प्रमुख रूप से हमारा ध्यान विकास और सामाजिक–आर्थिक न्याय के आसपास रहेगा।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मैं 'आर्म्ड फोर्सेस (स्पेशल पावर) एक्ट' तथा उत्तर–पूर्व के लोगों की इसे निरस्त करने की मांग के बारे में पार्टी में चर्चा कर इसके समाधान पर विचार करूंगा।

उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक्ट का मुद्दा एवं प्रभाव अलग–अलग है। हम निर्दोष लोगों की हत्याओं और मानवाधिकार के उल्लंघन की तीव्र निंदा करते हैं।

भाजपा के ''विजन–2025'' के बारे में श्री गडकरी का कहना था कि पार्टी मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी, विश्व–स्तरीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र, अनेक प्रकार के तकनीकी तथा व्यावसायिक कैरियर संस्थानों तथा पर्यटन क्षेत्र के विकास तथा सड़क अवसंरचनाओं जैसी कुछ परियोजनाओं को शामिल करेगी।

श्री गडकरी ने आगे कहा कि भाजपा जाति, मत और धर्म से ऊपर उठकर अलग किस्म की एक पार्टी है। हम देश में भाजपा शासित राज्यों में अपने किसी भी नौ राज्यों में अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। हम आतंकवादियों तथा आतंकवादी संगठनों के बेहद खिलाफ है।

उन्होंने फिर कहा कि कांग्रेस–नीत सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट (एसपीएफ) सरकार सभी मामलों में विफल रही है और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा कि यदि हम केन्द्र में सत्ता में आते हैं तो भ्रष्ट मंत्रियों की जांच करायेंगे तथा उन्हें दण्ड दिलाएंगे उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा–नीत एनडीए आगामी लोकसभा चुनावों में विजय प्राप्त करेगा।

पूर्वोत्तर के विकास पर अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में पानी, बिजली, परिवहन और संचार व्यवस्था पर हम अपने एजेण्डे पर रखेंगे। पूर्वोत्तर के समग्र विकास पर उनका कहना था कि पार्टी प्रतिवर्ष इस एजेण्डा पर सम्मेलन बुलाएगी और एक विशेष भाजपा संसदीय दल की टीम संसद में इस क्षेत्र के मुद्दों को उठाती रहेगी।

उन्होंने आगे कहा कि शांति कायम किए बिना विकास संभव नहीं है, इसलिए भाजपा शांति कायम करने के लिए हर

उपाय करेगी।

हमने मध्य प्रदेश में ''पब्लिक सर्विस एकाउंटेबिलिटी एक्ट'' नाम का एक नया एक्ट बनाया है जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनसे सरकारी अधिकारियों के लिए अनिवार्य हो गया है कि वे लोगों द्वारा मांगे गए किसी भी दस्तावेज की प्रतियां पन्द्रह दिनों में उपलब्ध कराएं अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी को प्रतिदिन 200 रूपए के हिसाब से जुर्माना देना होगा।

उन्होंने कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मांग पर की गई हड़ताल पर कार्रवाई न करने पर गहरी चिंता व्यक्त की।

श्री गडकरी की मणिपुर का यह पहला दौरा था और उन्होंने भी ज्ञानचन्द्र ओपन एयर थियेटर में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. नजमा हेप्पतुल्ला, राष्ट्रीय महासचिव श्री तापिर गाव एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी, पूर्वोत्तर राज्य संगठन मंत्री श्री पी. चन्द्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष श्री शांति कुमार शर्मा भी साथ थे। श्री गडकरी ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लिया।■

भाजपा ने पत्रकारों तथा गैर-पत्रकार कर्मियों के वेतन बोर्ड के कार्यान्वयन की मांगों का पूर्ण समर्थन किया

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी द्वारा 13 दिसम्बर 2011 को जारी प्रेस विज्ञप्ति

Hkkजपा अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने ''कंफिड्रेशन आफ न्यूज एजेंसी इंप्लाइज आर्गेनाइजेशन' को आश्वस्त किया कि भाजपा समाचार पत्रों तथा समाचार पत्र एजेंट संगठन के पत्रकारों तथा गैर–पत्रकार कर्मचारियों के वेतन बोर्ड के तुरन्त कार्यान्वयन का पूरी तरह से समर्थन करती है। श्री गडकरी के शिष्टमण्डल को कहा कि हम सरकार से इस विषय पर बात करेंगे और आग्रह करेंगे कि वह दोनों वेतन बोर्डों की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर समाचार–पत्रों के मालिकों से लागू करने के लिए कहे। फेडरेशन के एक शिष्टमण्डल ने श्री गडकरी के निवास पर मुलाकात की और उनसे दोनों वेतन बोर्डों की सिफारिशों की स्वीकृति पर 11 नवम्बर 2011 को जारी सरकारी अधिसूचना सम्बन्धी नवीनतम स्थिति से अवगत कराया। शिष्टमण्डल की शिकायत थी कि समाचार–पत्र उद्योग के मालिक इनका कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उद्योग के लाखों कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को अत्यधिक कठिनाईयां पेश आ रही हैं। उनका आरोप था कि समाचार–पत्र उद्योग के मालिक भारतीय समाचारपत्र सोसाइटी (आईएनएस) पर दबाव डाल रहे हैं कि एवार्ड को कार्यान्वित न किया जबकि वास्तविक स्थिति यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन मालिकों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है। शिष्टमण्डल ने श्री गडकरी को यह भी बताया कि विपक्ष की प्रमुख पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम आपसे इस विषय पर हस्तक्षेप का आग्रह करते हैं और सरकार को समाचार पत्र उद्योग के मालिकों के साथ इस विषय पर विचार करने के लिए सरकार को बाध्य करने का आह्वान करते हैं।

शिष्टमण्डल में सर्वश्री एम.एस. यादव (महासचिव, कंफिड्रेशन आफ न्यूजपेपर एंड न्यूज एजेंसी इम्पलाइज आर्गेनाइजेशन), राजेन्द्र प्रभु और एन.के. तिरखा (एनयूजे–आई), सुरेश अखौडी (प्रेजीडेण्ट), इण्डियन जर्नलिस्ट यूनियन, मदन तलवार, महासचिव, आल इण्डिया न्यूज पेपर इम्पलाइज फेडरेशन और सी.एस नायडू (महासचिव, इण्डियन एक्सप्रेस इम्पलाइज यूनियन) शामिल थे। ■

भाजपा-अकाली दल ने चण्डीगढ़ नगर निगम के चुनाव जीते

चण्डीगढ़ नगर निगम के चुनावों में भाजपा–अकाली दल गठबंधन ने कांग्रेस को झटका दिया है। 19 दिसम्बर 2011 को परिणामों की घोषणा हुई। पंजाब में होने वाले चुनावों से लगभग डेढ़ महीने पूर्व कांग्रेस की यह हार सामने आई है जिसमें उक्त कार्पोरेशन के 26– सदस्यों के आम परिषद में 2006 में प्राप्त 14 सीटों में से 11 सीट तक कांग्रेस सीमित हो गई हैं, भाजपा की सीटें 6 से बढ़कर 10 हो गई हैं। इससे भाजपा–अकाली दल गठबंधन की बोर्ड में बहुमत बनने की संभावना है। बीएसपी ने भी दो सीटें जीती हैं तो एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है।

'कांग्रेस शासन में घोटालों से घिर गया है देश'

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती और सपा नेता मुलायम सिंह यादव पर बरसते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों से दुखी है और इस बार चुनाव में भाजपा को जनादेश देकर सेवा का अवसर देगी। वहीं, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भाजपा की मांग पर शहरी इलाकों से पेट्रोल व डीजल पर चुंगी माफ करने की घोषणा कर समर्थकों में नया जोश भर दिया।

श्री गडकरी 24 दिसम्बर 2011 को जालंधर में भाजपा की प्रदेश स्तरीय रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया। राहुल गांधी की भी जमकर खिंचाई की और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी उत्तर प्रदेश के विकास को गंभीरता से नहीं लिया। श्री गडकरी ने कहा कि राहुल गांधी बयान दे रहे हैं कि अब मुलायम की दादागिरी नहीं चलेगी।

मैं कहता हूं कि अगर मुलायम की दादागिरी चलती है तो क्या मायावती का हाथी नोट नहीं खाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता दोनों से दुखी है। इसलिए वहां जनता इस बार भाजपा को जनादेश देगी। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के मामले को लेकर भी राहुल की जमकर खिंचाई की और कहा कि नई दिल्ली में लक्ष्मी दर्शन काम कांग्रेस की अगुवाई में सालों से चल रहा है। कामनवेल्थ गेम्स से लेकर 2जी तक के कई घोटालों से देश घिर गया है। इसके बाद भी राहुल गांधी भ्रष्टाचार के खिलाफ किस मुंह से बोल रहे हैं? कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश को भुखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार के अलावा दिया ही क्या है? उन्होंने डालर के मुकाबले रुपये की लगातार कम हो रही कीमत को लेकर भी केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया।

श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार जिन राज्यों में दूसरे राजनीतिक दलों या भाजपा की सरकार होती है उनकी मदद नहीं करती है। इसके लिए उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का धन्यवाद भी किया कि बादल हमेशा राज्यों के स्वायत्तता के अधिकारों को लेकर लड़ते रहे हैं। उन्होंने अन्ना हजारे व लोकपाल बिल को लेकर कहा कि कांग्रेस दबाव में लोकपाल बिल ला रही है, लेकिन उसकी चाबी अपने हाथ में रखना चाहती है। उन्होंने काले धन के मामले में कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार केन्द्र में आने के बाद काला धन एकत्र करके विदेशी बैंकों में जमा करने वालों की सूची जारी की जाएगी और काला धन देश में वापस लाया जाएगा। चूंकि लिस्ट में कांग्रेसियों के काफी नाम हैं इसलिए केंद्र सरकार यह लिस्ट जारी नहीं कर रही है। इस मौके पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेतली, मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने रैली को संबोधित किया।

राज्य के मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल ने भाजपा की मांग पर शहरी इलाकों से पेट्रोल व डीजल पर चुंगी माफ करने की घोषणा करके नया जोश भर दिया। स. बादल ने बताया कि उन्होंने इसका आदेश चंडीगढ़ से चलने से पहले ही जारी कर दिया है। इससे शहरियों को भी पेट्रोलियम पदार्थों में करीब 2 फीसदी राहत मिलेगी। सभा को सांसद स. नवजोत सिंह सिद्धू ने भी संबोधित किया।■

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित

चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड सहित पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों का 24 दिसम्बर 2011 को ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सात चरणों में मतदान होगा। पांचों राज्यों में मतगणना एक साथ चार मार्च को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरेशी ने पांचों राज्यों के चुनाव कार्यक्रमों का ब्यौरा देते हुए यहां संवाददाताओं से कहा कि इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता आज से ही लागू हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होगा। इनके तहत 4 फरवरी, 8 फरवरी, 11 फरवरी, 15 फरवरी, 19 फरवरी, 23 फरवरी, 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बाकी सभी राज्यों में सिर्फ एक चरण में मतदान होगा। ये राज्य हैं– पंजाब (30 जनवरी), उत्तराखंड (30 जनवरी), गोवा (3 मार्च) और मणिपुर (28 जनवरी)। सभी राज्यों में मतगणना चार मार्च को होगी।

श्री कुरैशी ने बताया कि अधिकतर मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र बन गये हैं और मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से होगा। मतदाताओं, मतदान केन्द्रों, वोटिंग मशीनों और चुनाव स्टाफ की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों की पर्याप्त तैनाती की जाएगी।

कुरैशी ने बताया कि उत्तरप्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटों के लिये चुनाव होगा। पहले चरण के तहत 60 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान चार फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 55 सीटों के लिये आठ फरवरी, तीसरे में 59 सीटों के लिये 11 फरवरी, चौथे में 56 सीटों के लिये 15 फरवरी, पांचवें में 56 सीटों के लिये 19 फरवरी, छठे में 49 सीटों के लिये 23 फरवरी और सातवें तथा अंतिम चरण में 68 सीटों के लिये 28 फरवरी 2012 को मतदान होगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिये मतदान 30 जनवरी 2012 को होगा और उत्तराखंड के सभी 70 विधानसभा सीटों के लिये भी इसी दिन मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर सकेंगे। कुरैशी ने बताया कि गोवा के 40 विधानसभा सीटों के लिये मतदान तीन मार्च 2012 को होगा जबकि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों के लिए 28 जनवरी को।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राज्यों की विधानसभा सीटों के लिये मतगणना एक साथ चार मार्च 2012 को होगी। उन्होंने बताया कि सभी राज्यों में मतदाता सूचियों को संशोधित किया जा रहा है और अंततः दो जनवरी 2012 को इसे प्रकाशित किया जाएगा। फिलहाल उत्तरप्रदेश में 11 करोड़ 19 लाख 16 हजार 689 लोगों के नाम मतदाता सूची में हैं, पंजाब में एक करोड़ 74 लाख 33 हजार 408 मतदाता, गोवा में दस लाख 11 हजार 675, मणिपुर में 16 लाख 77 हजार 270 तथा उत्तराखंड में 57 लाख 40 हजार 148 मतदाता हैं। कुरैशी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। अधिकांश वोटरों के पास फोटो पहचान पत्र हैं। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों से कोई छेड़छाड़ नहीं हो पाये, इसके लिये इनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इन मशीनों की जांच की व्यवस्था भी की जाएगी। ■